इस अंक के साथ आठ पृष्ठों का परिशिष्ट भी हैं

# सीटू मजदूर

वर्ष 4 अंक 4 | अप्रैल 1982 | 50 पैसे

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

# संकट की काली छाया

भारतवर्ष में पूंजीवादी विकास करने की दिवालिया नीति ठहराव की स्थिति में पहुंच चुकी है. संकट की काली छाया न केवल देश की अर्थ-व्यवस्था बल्कि सम्पूर्ण राज्यतंत्र को ग्रस रही है और जनता विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के कर्जो के कड़वे फलों को भी देख रही हैं.

संकट इतना स्पस्ट है कि राष्ट्रपति ने अपने इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के सम्बोधन में कुछ असफलताओं की तरफ इंगित किया और कहा :

"विकास के फल अधिकांश लोगों की पहुंच के बाहर हैं. बेरोजगारी तथा अंशकालिक रोजगार की समस्यायें अभी भी हमें घेरे हुए हैं. प्रति व्यक्ति आय अथवा आवश्यक सामग्रियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में हुई वृद्धि हमारे द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से बहुत कम है."

उन्होंने आगे कहा: "यदि हम शीघ्र ही सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यो की अवमानना को रोकने के लिए कार्यवाही नहीं करते हैं तो हमारी राजनैतिक व्यवस्था से जनता का विश्वास उठता जायगा.

परन्तु सरकार ने संसद के वजट सत्र से पूर्व राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से एक अच्छी तस्वीर पेश करने की कोशिश की है. सरकार द्वारा प्रस्तुत सन 1981-82 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस बात को दिखाने का प्रयास किया गया है कि मूल-संरचना में पहले की बाधाओं को समाप्त कर दिया गया है और अब अर्थव्यवस्था उन्नति कर रही है. यह दावा किया गया कि औद्योगिक उत्पादन में 80-81 की 4% की वृद्धि तथा 79-80 की 1.4% की गिरावट की तुलना में वर्ष 81-82 में 8% की वृद्धि की संभावना है. ठीक इसी तरह यह भी दावा किया गया है कि वास्तविक कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वर्ष 81-82 में 4.5% ऊंची वृद्धि होगी और इस तरह छठी पंचवर्षीय योजना द्वारा निर्धारित 5.2% वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य को पार कर जायगी.

## झूठा दावा

आधार वर्ष 1979-80 अपवादस्वरूप खराब वर्ष रहा जब कि कृषि, औद्योगिक तथा कुल राष्ट्रीय उत्पादन में क्रमशः 15.5%, 1.4% तथा 4.8% की गिरावट आयी. अतः आर्थिक स्थिति पर संतुष्ट होना भ्रामक है; विशेषरूप से क्योंकि गतिरोध के लक्षण बहुत स्पष्ट दीख रहे हैं. उदारणार्थ अप्रैल नवंबर 81 में औद्योगिक उत्पादन में 9.8% की वृद्धि हुई जो कि वर्ष 80 के उसी समय से ज्यादा है, लेकिन संपूर्ण वर्ष 81-82 में कुल वृद्धि-दर केवल 8% ही रही. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस वृद्धि-दर को वरकरार रखा जा सकता था. स्वयं आर्थिक सर्वेक्षण में निहित अन्तर्विरोध यह संदेह पैदा करते हैं तथा बहुत ही कम आशा प्रदर्शित करते हैं. सरकार ने इस वर्ष को "उत्पादकता वर्ष" घोषित करके केवल इसी संदेह को सुनिश्चित किया है.

## मजदूर पैदा करते हैं और मरते हैं

इस बात पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि वर्ष 81-82 में विकास मात्र से संबंधित है, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे आंतरिक बाजार, राष्ट्रीय संपत्ति के बंटवारे, रोजगार पैदा करने तथा रहन-सहन के स्तर में परिवर्तन आदि के महत्व को कम करता है. संसद-सदस्य तथा सीटू सचिव ई बालानन्दन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि स्वयं सरकारी आकड़े यह बताते हैं कि वर्ष 1971 से 81 के बीच केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 7% से लेकर 46% तक की कटौती हुई है. इन्हीं वर्षों में कारखानों तथा खेतिहर मजदूरों के वेतन क्रमशः 10% और 40% कम हुए हैं जबकि सबसे बड़े 20 इजारेदार परिवारों की कुल संपति जो कि 1972 में 3071.98 करोड़ थी, सन 1799 में 6615.69 करोड़ हो गई. उन्होंने बताया कि इस उत्पादन वृद्धि से मजदूरों ने अपने वास्तविक वेतन में नुकसान उठाया जब कि इजारेदारों ने अपनी संपत्ति और मुनाफा में काफी इजाफा किया. उन्होंने कहा कि मजदूर पैदा करते हैं और मरते हैं जबकि मालिक उनके श्रम के फलों को छीन लेते हैं और आनंद मनाते हैं.

## बेरोजगारी

सेवा योजन केन्द्रों के रजिस्टरों में रोजगार के इच्छुकों की संख्या एक करोड़ 70 लाख को पार कर चुकी है. सन 81 के अंत तक गांव के बेरोजगारों को मिलाकर कुल संख्या 5 करोड़ पहुंच चुकी है. यह सर्वेक्षण उनके लिए कोई आशा नहीं बंधाता और

पेज दो पर

दूसरी तरफ रिजर्व बैंक तथा रेलवे में कंप्यूटर लगाने का अभियान चलाया जा रहा है.

## औद्योगिक बीमारी

दूसरी तरफ आर्थिक सर्वेक्षण बीमारी के संदर्भ में खतरनाक स्थिति का जिकर करता है. जून 1980 की 345 बड़ी बीमार इकाइयों की तुलना में सन 81 में इनकी संख्या 389 थी. इसी दौरान मध्यम आकार की बीमार इकाइयों की संख्या 1013 से 1026 हो गयी तथा छोटे आकार की इकाइयों की संख्या 20326 से 22325 हो गई. दिसंबर 81 के अंत तक बीमार छोटी इकाइयों की संख्या 23255 हो गई. आर्थिक सर्वेक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि 52% बड़ी औद्योगिक इकाइयों की बीमारी का कारण आंतरिक है जैसे प्रबंध में कमी कोष को अन्यत्र ले जाना, स्पष्ट व्यापारिक रणनीति की कमी और विभिन्न हितों में आंतरिक टकराव आदि. यह भी स्वीकार किया गया है कि बाजार की मंदी, बिजली और कोयले की कमी तथा यथोचित यातायात सुविधाओं का उपलब्ध न होना आदि भी औद्योगिक बीमारी के कारण रहे हैं. यह भी स्वीकार किया गया है कि सन 80 में 4 तथा 81 में केवल 2 इकाइयों का अधिग्रहण किया गया परंतु वर्ष 81-82 में एक भी इकाई का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया. बीमार इकाईयों को पुनः जीवनदान देने के लिए कार्यभार बढ़ाकर मजदूरों की संख्या कम करने तथा श्रमिकों का वेतन कम करने के लिए अथक अभियान चलाया जा रहा है. कोई नहीं जानता कि कितने मजदूर इसकी चपेट में है.

## प्रचंड मुद्रास्फीति

यह दावा किया गया है कि मुद्रास्फीति को जनवरी 80 में 23.3% से जनवरी 81 में 15.9% तक तथा जनवरी 82 में 4.9% तक नीचे लाया गया है. जहां तक करोड़ों-करोड़ साधारण जनता का संबंध है वे हर चीज महंगी पा रहे हैं. औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960—100) जो कि जनवरी 80 में 371 था वह जनवरी 81 तक 411 और दिसंबर 81 तक 460 पर पहुंच गया. इस प्रकार वर्ष 1979-80 में 12.5% 80-81 में 9.4% तथा दिसंबर 81 तक 9.5% की वृद्धि हुई. आर्थिक सर्वेक्षण इस अंतर्विरोध की यह तर्क देकर व्याख्या करता है कि दो प्रकार की सूचियों के लिए अलग-अलग महत्व दिया जाता है. सर्वेक्षण यह स्वीकार करता है कि खाद्यान्नों, खाद्य तेलों, फलों, सब्जियों, दूध व दूध से बने सामानों, अण्डा, मछली, मांस आदि की कीमतें लगातार बढ़ती रही हैं. अतः जनसाधाण जो कि अपनी आमदनी का 80% खाने पर खर्च करने के लिए मजबूर हैं जीवनयापन में अत्यंत कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं. संसद के बजट-सत्र से ठीक पहले सरकार ने डालडा की कीमत में 10% वृद्धि की इजाजत दी है जो कि पुनः मूल्य-वृद्धि का कारण बनेगा.

## जनता पर और कर

ऐसी स्थिति में सरकार ने जनता पर 1300 करोड़ रुपयों का और ज्यादा भार इस तरीके से डाल दिया है जिसे आल इंडिया इन्स्योरेंस इम्प्लाइज यूनियन के संयुक्त महामंत्री तथा संसद सदस्य सुनील मोइत्रा ने "किस्तों में बजट" की संज्ञा दी है. संसद के पिछले अधिवेशन में रेलमंत्री ने रेल के माल-भाड़े और किराये में वृद्धि करके 400 करोड़ रुपयों का बोझ डाल दिया था (1981-82 के लिए 80 करोड़ तथा 82-83 के लिए 320 करोड़) और अब वर्तमान रेलमंत्री ने 267 करोड़ की ओर बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है. बजट से ठीक पहले सी. एम. स्टीफेन ने टेलीफोन टेलीग्राम तथा अन्य चीजों की कीमतें 100 करोड़ बढ़ा दी है तथा इस बजट के दौरान 622 करोड़ रुपयों का कर और लाद दिया गया है.

## आर्थिक सहायता में कमी-कीमतों में वृद्धि

यह बजट खाद्य पदार्थों पर पिछले वर्ष की तरह केवल 700 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता करता है जो कि वास्तविकता में कटौती है. खादों पर आर्थिक सहायता पिछले वर्ष में 679 करोड़ की जगह इस वर्ष 386 करोड़ कर दी गई है जो कि वास्तव में बहुत कम है. युरिया की कीमत 2000/ प्रति टन से 2350/ प्रति टन कर दी गई है. सीमेंट पर उत्पादन शुल्क में 100% वृद्धि का प्रस्ताव है तथा दो मूल्य की नीति चालू की जा चुकी है. समाचारपत्रों में छपी खबरों के अनुसार कोयला तथा बिजली आदि की कीमतें बढ़ाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है जो कि ठीक बजट-सत्र के बाद लागू किया जायगा और इससे इंकार नहीं किया गया है.

## खुशामदी के उपाय

यह सब उस विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीम मुद्राकोष, को खुश करने के खुशामदी उपायों के सिवा और कुछ भी नहीं है, जिन्होंने भारत सरकार पर कर्जों के लिए न केवल शर्मनाक शर्तें थोप दी है बल्कि उन शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपने रखवाले भी भेज दिये हैं. जनवरी माह में तिन थुम के नेतृत्व में अंतर्रास्ट्रीय मुद्राकोष की एक टीम तथा फरवरी में विश्वबैंक के प्रमुख क्लासन ने हमारे देश का भ्रमण किया: सरकार द्वारा बहुत बार इंकार किये जाने के बावजूद बजट पर विश्वबैंक तथा अन्तर्रांस्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्ज की शर्तों की छाप साफ-साफ दिखाई पड़ती है और लोग कड़वे फलों को देख रहे हैं.

## वेतन-जाम के उपाय

सरकार के द्वारा अपनाया गया एक और उपाय वेतन-जाम की ओर एक कदम है. विलम्बित भुगतान के सिद्धांत तथा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की उपार्जित उपलब्धियों को खतम करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है. इस्पात उद्योग में वेतन-वृद्धि को उत्पादकता से जोड़ने वी बात की जा रही हैं. जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन और बोनस मनमानी ढंग से निश्चित करने का अधिकार पहले ही मान लिया गया है. वेतनभोगी मजदूरों की तनख्वाहों पर आक्रमण लगातार बढ़ रहा है. एक सूचना के अनुसार वित्तमंत्री ने राज्य सरकारों को सलाह दिया है कि वे केंद्र से परामर्श के बिना अपने कर्मचारियों के वेतनों में भारी सुधार का कोई कदम न उठाएं.

## भुगतान रिक्तियों का संतुलन

यह सब भुगतान घाटे को पूरा करने के लिए अपनाया गया

शेष पृष्ठ तेरह पर

# कोयला मजदूरों द्वारा देशव्यापी संघर्ष की तैयारी

आल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन की बैठक २, ३ मार्च को एम ए. हास्टल, नागपुर में हुई जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र तथा टिस्को मालिकान पर नये वेतन-समझौते के लिए दबाव डालने हेतु कोयला उद्योग में देशव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया गया. वर्तमान समझौता 31 दिसंबर से समाप्त हो रहा है. फेडरेशन ने देश के समस्त कोयला-मजदूरों का एक नया मांगपत्र तैयार करने तथा मांगों पर विचार विमर्श करने, और पिछले समझौते की सभी धाराओं को लागू करवाने हेतु आंदोलन करने के लिए प्रत्येक खान पर सभा करने का निर्णय लिया है.

इस बैठक की अध्यक्षता फेडरेशन के अध्यक्ष एम. के. पंधे ने की तथा रानीगंज, आसनसोल, राँची, झरिया, धनवाद, कोरबा, विश्रामपुर, चिरीमिरी, सिगरेरी, वर्धा घाटी, नागपुर कोल फील्डस तथा सी. एम. पी. डी. आई. कार्यालय कलकत्ता के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

बैठक में कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय कमेटी से इंटक द्वारा अपने प्रतिनिधियों को वाहर कर लेने पर चिन्ता व्यक्त की है जिसके कारण उद्योग में द्विपक्षीय मंच की कार्यवाहियां शमाप्त हो गई हैं यद्यपि कि मालिकान पिछले समझौते को पूरी तरह लागू करने में असफल रहे हैं. इंटक ने अपने इस कदम से कोयला मालिकान को 6 लाख कोयला मजदूरों की समस्याओं पर एकतरफा निर्णयों को जारी रखने में केवल मदद ही पहुंचाया है. बैठक ने इंटक के नेताओं से अपने इस आत्मघाती निर्णय को वापस लेने तथा द्विपक्षीय कमेटी में शामिल होने के लिए अपील करने का निर्णय किया है जिससे कि कोयला मजदूरों के बकाया मामले बिना देरी के लागू किए जा सकें.

बैठक ने 19 जनवरी की देशव्यापी हड़ताल के लिए कोयला मजदूरों को बधाई दी है और सेण्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के मालिकान के प्रतिशोधात्मक रवैये एवं सी. एम. पी. डी. आई. एल. की, हड़ताल में भाग लेने के लिए 8 दिन का वेतन काट लेने की धमकी के लिए भर्त्सना की है. बैठक ने इन कार्यवाहियों को वापस लेने की मांग की है तथा कोयला मजदूरों से इन बदले की कार्य-वाहियों के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करने का आह्वान किया है.

बैठक ने एक प्रस्ताव के द्वारा केन्द्रीय सरकार के बजट द्वारा डाक व तार की कीमतों पर भारी कर और अतिरिक्त लेवी थोपने तथा रेल के किराए एवं माल भाड़े में वृद्धि की निंदा की है तथा कोयला मजदूरों से इन कार्य-वाहियों का विरोध करने का आह्वान किया है.

एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा बैठक ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 16 उद्योगों को आवश्यक घोषित करने वाली अधिसूचना की निन्दा की हैं तथा उसे वापस लेने की मांग की है.

बैठक ने विभिन्न केन्द्रों पर यूनियन की गतिविधियों की समीक्षा की तथा संगठन को कारगर बनाने के लिए कदम उठाने एवं कोयला मजदूरों के संघर्षों को पूरे देश में लोकप्रिय बनाने के लिए एक बुलेटिन छापने का निर्णय लिया है.

## इस्पात उद्योग में उत्पादकता से जुड़े वेतन का विरोध

एटक के महामंत्री का० इन्द्रजीत गुप्ता तथा सीटू सचिव का० एम० के० पन्धे ने दि० २६ फरवरी को निम्नांकित बयान जारी किया।

इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति की दि० २४ व २५ फरवरी को हुई बैठक में स्टील आथारिटी आफ इण्डिया के प्रबन्ध पक्ष ने मजदूर पक्ष को इस बात का स्पष्ट संकेत दिया कि इस उद्योग में भविष्व में होने वाली कोई भी वेतन वृद्धि उत्पादकता से सम्बन्धित होगी तथा साथ ही भविष्य प्रभावी भी होगी न कि पूर्वप्रभावी. यह बयान वर्तमान संयुक्त समझौते की समाप्ति की तिथि दि० ३१-३-८२ तथा उसके बाद इनकी पुनः समीक्षा के संदर्भ में दिया गया।

दूसरे शब्दों में स्टील आथारिटी आफ इण्डिया के अधिकारियों ने सरकार और सार्वजनिक उद्योगों के ब्युरो के इशारों पर वेतन को उत्पादकता से जोड़ने तथा आगे किसी भी प्रकार की वेतन वृद्धि की पूर्व शर्त के रूप में उत्पादन को रखने की पूर्व सूचना स्पष्ट रूप से दी है।

यह सम्पूर्ण ट्रेड यूनियन आंदोलन के इस डर को ही प्रमाणित करता है कि केन्द्र सरकार उत्पादकता बढ़ाने के नाम पर मजदूर वर्ग पर वेतन जाम थोपने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ है। १९ जनवरी की आम हड़ताल के पीछे प्रमुख तर्कों में से यह एक था।

वेतन को उत्पादकता से जोड़ना, भारी कार्यभार थोपने, श्रम को धनीभूत करने, और श्रम की लागत को कम करने का ही दूसरा नाम है। इसके अतिरिक्त यह प्रमाणित सत्य है कि इस्पात जैसे जटिल उद्योग में उत्पादन और उत्पादकता मुख्य रूप से स्वयं मजदूरों के प्रयासों पर निर्भर नहीं है। वास्तव में सरकार की स्वयं स्वीकृति के अनुसार इस्पात उद्योग में उत्पादन लक्ष्य मूल संरचनात्मक त्रुटियों के कारण पूरे नहीं हो पा रहे हैं उदाहरणार्थ, बिजली तथा कोयले की आपूर्ति रेलवे वैगनों का आवागमन आदि। इस्पात उद्योग में पूरी भरपायी के अभाव में समझौते के इन वर्षों में मजदूरों के वास्तविक वेतन और भी कम हुए हैं।

अतः ट्रेड यूनियन आम्दोलन वेतन को उत्पादकता से जोड़ने के इस सिद्धान्त और व्यवहार का मूलतः विरोधी है। यह पूंजीवाद का प्रिय मदारी का खेल है जिसे टाटा और स्टील आथारिटी आफ इण्डिया एक समान आयना रहे है।

# ब्रिटिश हाई कमीशन पर प्रदर्शन

ब्रिटिश लोको कर्मचारियों के संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करके आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा तार भेजने के बाद तमाम लोको कर्मचारियों और अन्य रेल मजदूरों ने 5 मार्च को दिल्ली स्थित ब्रिटिस हाई कमीशन पर प्रदर्शन किया. इस एकजुटता की कार्यवाही को संगठित करने का निर्णय दि० 20 फरवरी को धनवाद में हुई 12 मैन पैनल की बैठक में लिया गया था.

ब्रिटिस हाई कमिश्नर को दिए गये स्मरण-पत्र में कहा गया है कि "हम ब्रिटिश रेलवे बोर्ड द्वारा वेतन पुनरीक्षण सम्बन्धी समझौते को जो कि बिना शर्त है तथा जिसका अन्य समझौतों से कोई सम्बन्ध नहीं है, लागू करने से इंकार करने का विरोध करते हैं. यह कार्यवाही सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया की जड़ को ही काटती है. हम इस मामले में आपकी सरकार द्वारा ब्रिटिस रेलवे बोर्ड को समर्थन दिए जाने का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि समझौते को लागू करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जांय."

आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के महासचिव एस. के धर ने एसोसिएटेड सोंसाइटी आफ लोको-मोटिव इन्जीनियर्स एण्ड फायरमेन, लन्दन, के महासचिव रे वक्तन को लिखे गये अपने 23 फरवरी के पत्र में भारत में परिस्थितियों का विस्तार से जिकर किया है तथा कहा है कि "भुक्तभोगी होने के कारण आपके संघर्ष में हमारा दिल आपके साथ है." उन्होंने संघर्ष की वर्तमान स्थिति की जानकारी पाने की इच्छा व्यक्त की है जिससे कि लोको कर्मचारी एकजुटता के साथ समर्थन के अन्य तरीकों पर विचार कर सकें. ब्रिटिश लोको कर्मचारि योकी जीत हो जाने के कारण दि० ८ मार्च को कलकत्ता में होने वाला प्रदर्शन विजय-दिवस में परिवर्तित हो गया.

## आल इन्डिया रेलवेमेन्स फेडरेशन की कार्यकारिणी की बैठक

ज्ञात हुआ है कि ए. आई. आर. एफ. की कार्यकारिणी ने, जिसकी बैठक दि० 16-17 फरवरी को नई दिल्ली में हुई, वकाया मंहगाई भत्ते के देर से भुगतान करने तथा नगर-भत्ता और मकान भत्ते को जमा रखने के प्रस्ताव को बहुमत से स्वीकार कर लिया है. तीन सदस्यों ने इसके खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया है.

## 12 मैन पैनल द्वारा एकता की कोशिश

कैटेगरिकल संगठनों के 12 मैन पैनल की बैठक दिनांक 20 फरवरी को धनबाद में हुई. 19 जनवरी की ऐतिहासिक हड़ताल में रेल मजदूरों को हिस्सा लेने से रोकने वाली तमाम कमजोरियों पर विचार करने के बाद रेल कर्मचारियों की एकता को मजबूत बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास करने का निर्णय लिया तथा प्रत्येक इकाई को तीन माह के अन्दर ठोस सुझाव भेजने का आदेश दिया है.

पैनल ने 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक "दमन विरोधी सप्ताह" मनाने और अन्तिम दिन मण्डल प्रबन्धक कार्यालयों पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है. यह भी निर्णय लिया गया कि बाकी 4 रेलों में संयुक्त दौरे का कार्यक्रस पूरा किया जायगा.

एक प्रस्ताव पास करके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 320 अंकों पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला देने के बाद नगर तथा मकान भत्ते और महंगाई भत्ते की बकाया धनराशि को जमा रखने के प्रस्ताव की निंदा की है तथा सभी मजदूरों से इसका विरोध करने का आह्वान किया है.

## कनफेडरेशन का वार्षिक अधिवेशन

आल इण्डिया रेलवे इम्प्लाईज कनफेडरेशन की वार्षिक आम सभा दि० 21-22 फरवरी को धनवाद में हुई जिसमें 800 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. सरकार की दमनात्मक नीतियों के बावजूद सभी इकाइयों के प्रतिनिधियों की सक्रिय हिस्सेदारी के कारण अधिवेशन सफल रहा. सी. एम. सिंह कनफेडरेशन के अध्यक्ष तथा एन. एस. भंगू पुनः महामंत्री चुने गये. सीटू अध्यक्ष का० बी. टी. रणदिवे ने अपना शुभकामना सन्देश भेजा. आम सभा को आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के महासचिव का० एस. के. धर तथा दूसरे साथियों ने भी सम्बोधित किया.

## 14 (II) में दमन की कार्यवाही रद्द घोषित

केरला हाई कोर्ट ने केस नं. ओ.पी. एन. 4781/81 में दि० 1 फरवरी को दिए गये फैसले में दक्षिण रेलवे के श्री के. एस. सुब्रह्मण्यम, ग्रेड बी ड्राइवर, की बरखास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है तथा रेल अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे कर्मचारी को पिछले वेतन के साथ नौकरी में लें तथा बरखास्तगी के समय के बराबर पद पर रखे. अवेदक को 500 रु० मुकदमे के खर्च दिये जाने का भी आदेश दिया गया है.

## सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहतका आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने सी. एम. पी. नं5687/82 और टी. पी. (सिविल) नं 210/81 में दि० 3 मार्च के एक आदेश के द्वारा रेल प्रशासन को आदेश दिया है कि वे मामलों के विचाराधीन रहने तक आवेदकों को उनके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के बराबर धनराशि अन्तरिम सहायता के रूप में दें जिसका उनके भविष्य निधि खाते से कोई संबंध नहीं होगा. कर्मचारियों से काम लेना या न लेना रेल प्रशासन की मर्जी पर छोड़ दिया गया है. यदि वे काम नहीं लेना चाहते हैं तो यह उनकी मर्जी है परंतु उन्हें अंतिम वेतन देना होगा."

करतारचंद और अन्य द्वारा चण्डीगढ़ और जोधपुर उच्च न्यायालयों में दाखिल याचिकाओं को भारत सरकार ने एक याचिका के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में स्थानान्तरित किया था. रेल प्रशासन ने उनकी भविष्य निधि की राशि समाप्त हो जाने के बहाने उनको वेतन देना बंद

पेज पंद्रह पर

# रेलवे माल भाड़े और किराए में वृद्धि की सीटू द्वारा निंदा

सीटू अध्यक्ष का० बी. टी. रणदिवे तथा महामंत्री और संसद सदस्य का० पी राममूर्ति ने दि० 24 फरवरी को निम्नांकित बयान जारी किया :

सीटू रेलमंत्री द्वारा दि० 23 फरवरी को संसद में घोषित 261.45 करोड़ रुपयों की हद तक अतिरिक्त वृद्धि के साथ रेल किराए तथा माल-भाड़े में वृद्धि की निन्दा करती है. रेलमंत्रालय ने ठीक दो बर्षों के दौरान रेल के किराए और माल-भाड़े में 1142 करोड़ रुपयों की वृद्धि थोप दी है, दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं पर परम्परागत दी जाने वाली छूट को भी वापस ले लिया गया है जिससे जन साधारण का जीवन और भी दयनीय हो जायगा. इससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तथा जनता की उपभोग क्षमता का स्तर ओर नीचे गिरेगा. यह सब विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के दवाब में किया जा रहा है जो बहुत दिनों से इन नीतियों को अपनाने के लिए भारत सरकार पर दबाव डाल रहे थे.

लागत पूंजी के अनुपात में कुल आमदनी जो कि वर्ष 1950-51 में 31.8% थी, 20 वर्षों तक लगभग स्थिर रही और वर्ष 73-74 में 29.22% हो गई. तब से इसमें लगातार वृद्धि होती रही और वर्ष 80-81 में 43.04% तक पहुंच गई. 81-82 तथा 82-83 के लिए प्रस्तावित वृद्धि के साथ इस अनुपात के 50% से भी ऊपर पहुंच जाने की सम्भावना है अर्थात 10 वर्षों से कम में 60% की वृद्धि हुई है. यह सरकार द्वारा विकास के लिए अपनाए एये पूंजी-वादी रास्ते और साम्राज्यवादी शक्तियों पर निर्भरता का ही परिणाम है.

अखबारों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार रेलवे बोर्ड के सेवा-निवृत्त अध्यक्ष श्री गुजराल ने, जिनका सेवाकाल विश्वबैंक के दवाव से बढ़ा दिया गया है, मासिक टिकटों पर भी वृद्धि का संकेत दिया है जिससे समस्त वेतनभोगी, छात्र, विक्रेता तथा उपनगरों में रहने वाले लोग प्रभावित होंगे और उनकी दुर्दशा और भी बढ़ेगी.

रेलमंत्री ने अपने बजट भाषण में ज्यादा से ज्यादा माल यातायात के लिए कम्प्यूटर लगाए जाने का भी संकेत दिया है जो कि न केवल देश की सेवायोजन क्षमता को कम करेगी वल्कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए तवाही पैदा करेगी इसका मतलव है रेलकर्मियों के ऊपर काम का बोझ बढ़ाना तथा दमन.

अतः सीटू मांग करती है कि सरकार आम जनता को लूटने की इस नीति को त्याग दे तथा रेल के किराए और माल भाड़े में प्रस्तावित वृद्धि को वापस ले ले. सीटू सरकार को अपनी जनविरोधी और मजदूर-विरोधी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर करने हेतु तमाम केन्द्रीय ट्रेड युनियनों तथा लोकतांत्रिक संगठनों से एकजुट होने तथा अपनी जोरदार आवाज उठाने की अपील करती है.

# पत्थर खदान मजदूरों की सफल हड़ताल

संथाल परगना माइन्स एण्ड क्वैरीज वर्कर्स यूनियन (सीटू) के आह्वान पर पाकुर विहार के 15000 पत्थर खदान मजदूरों ने दि० 14 जनवरी से अनि-श्चितकालीन हड़ताल कर दी और मालिकों को न्यूनतम वेतन तथा वोनस सहित अपनी छः सूत्री मांगें तै करने का वादा करने के लिए मजबूर कर दिया. 5 फरवरी को पाकुर के एस. डी. ओ. द्वारा सौहार्द्रपूर्ण समझौते के लिए हस्तक्षेप का लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद मजदूर काम पर लौटे. "अपनी मागों के लिए मजदूरों ने एक लम्वा संघर्ष छेड़ दिया था". केन्द्रीय श्रम मंत्रायल के इशारों पर मालिकों ने इंटक यूनियन के साथ कुछ समझौते किए थे. इसके खिलाफ मजदूरों ने अपने संघर्ष को और भीं तेज कर दिया तथा धरना, प्रदर्सन और एक दिन की हढ़ताल का आयोजन किया. मालिकों का एक हिस्सा सीटू यूनियन के साथ समझौते के लिए तैयार था परन्तु जिलाधिकारियों ने केन्द्रीय श्रममंत्रालय के इशारे पर ऐसा नहीं होने दिया और मजदूरों को अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजवूर कर दिया. इंटक के गुन्डों के साथ भारी मात्रा में पुलिस और सी. आर. पी. ने मजदूरों पर आक्रमण किया और पीटा जिससे युनियन के अध्यक्ष अव्दुल हकीम तथा महामंत्री कृष्णानन्द मण्डल सहित तमाम लोग घायल हो गये. बहुत से लोग गिरफतार कर लिए गये और अध्यक्ष तथा महामत्री के खिलाफ भी गिरफतारी के आदेश जारी किये गए जिससे उन्हे भूमिगत हो जाना पडा. दूर 2 के गांवों तक धारा 144 लगा दी गई. अधिकारियों ने साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काकर भी हड़ताल तोड़ने की कोशिस की. परन्तु निडर मजदूरों ने एकजुट संघर्ष चलाया और अन्त में मालिकों तथा एस. डी. ओ. को लिखित वादा करने के लिए मजवूर कर दिया. बिहार राज्य सीटू के महामंत्री चण्डी प्रसाद तथा युनियन के अध्यक्ष अब्दुल हकीम ने एक संयुक्त बयान में मजदूरों को संघर्ष के लिए बधाई दी हैं तथा मालिकों और एस. डी. ओ. से अपने वादे तुरन्त पूरे करने की मांग की है.

## मई 1982 अंक विशेषांक

मई 1982 का अंक बहुमूल्य लेखों तथा सूचनाओं सहित विशेषांक के रूप में निकाला जायगा. इसकी कीमत एक रुपया प्रति कापी होगी. परन्तु फिर भी वार्षिक ग्राहकों को अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी. अतिरिक्त प्रतियों के लिए आदेश 15 अप्रैल 1982 तक हमारे कार्यालय 6 तालकटोरा रोड के पत्ते पर भेजें.

# अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को असम जूट मिल पर सीटू की शिकायत

सीटू ने आसाम कोआपरेटिव जूट मिल्स लि०, सिलहट, के प्रबंधकों द्वारा संगठन बनाने की आजादी तथा सामूहिक सौदेवाजी के अधिकारों के उल्लंघन किए जाने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ में एक और शिकायत दर्ज की है. मजदूरों का एकमात्र संगठन 'असम को-आपरेटिव जूट मिल वर्कर्स यूनियन' पहले इंटक से सम्बद्ध थी और इसे प्रबन्धकों की मान्यता भी प्राप्त थी. परन्तु नेताओं की मालिकपरस्त नीतियों ने उन्हे मजदूरों से अलग कर दिया. और 1978 में हुई वार्षिक सभा में यूनियन ने भारी बहुमत से इंटक से सम्वद्धता समाप्त कर सीटू से सम्वद्ध होने का निर्णय किया.

इंटक के साथ मालिकों की सांठ गाठ तब खुलकर ऊपर आई जब कि उन्होने यूनियन की मान्यता खतम कर दी तथा अलग हुए ग्रुप के साथ दूसरी समानान्तर युनियन बनवाकर उसे शीघ्र ही मान्यता दे दी.

बहुमत प्राप्त सीटू युनियन के नेताओं तथा मजदूरों पर खुला अत्याचार शुरू हो गया. पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य उत्पीड़ित किए गये यूनियन ने श्रम विरोध का मामला उठाया. विवाद के विचाराधीन होने के दौरान मालिकों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा ३३ का उल्लंघन करके मजदूरों कीवरखा-तगी का काम जारी रखा. यहां तक कि मालिकान युनियन कार्यालय में बिजली की लाइन काट देने की हद तक पहुंच गये.

जब मजदूरों को सीटू से अलग कर देने के सभी उपाय व्यर्थ साबित हुए तब मालिकों ने इंटक गुंडों को मजदूरों में आतंक पैदा करने के लिए लगाया. असामाजिक तत्वों ने मजदूरों की एक सभा पर तेज धार-दार हथियारों से आक्रमण किया और बहुतों को घायल कर दिया. अन्त में गुण्डों ने युनियन कार्यालय का ताला जबर-दस्ती तोड़ दिया और कब्जा कर लिया. यहां तक कि बार बार शिकायतें किए जाने के बावजूद न तो पुलिस ने और न ही सरकार ने युनियन कार्यालय को उसके अधिकृत मालिकों अर्थात असम कोआपरेटिव जूट मिल वर्कर्स युनियन को दिलाने की कोई कोशिश की और न ही उन्होंने गुण्डों के खिलाफ कोई कार्यवाही की. बहुत सारे युनियन के नेता और सक्रिय कार्यकर्ता मालिकों के द्वारा लगाए गये गुण्डों के कारण अपने काम पर नहीं जा सकते थे जिससे शीघ्र ही या तो उन्हें वरखास्त कर दिया गया अथवा नौकरी छोड़कर चला गया हुआ घोषित कर दिया.

सीटू अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का ध्यान इन तथ्यों की ओर आकर्षित करती है जहां कि मजदूरों को अपनी केन्द्रीय ट्रेड युनियन चुनने के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा हैं. अतः वे प्रार्थना करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भारतवर्ष में ट्रैड यूनियन अधिकारों के अतिक्रमण के मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए एक टीम भेजे.

# एच. एस. सी. एल प्रशासन की देरी की नीति

एच. एस. सी. एल. का प्रशासन मजदूरों की मांगों पर वार्ता करने में देरी की नीति अपना रहा हैं जिससे मजदूरों में असन्तोष बढ़ रहा है.

दि० 17-18 नवम्बर 1981 को सम्पन्न द्विपक्षीय बैठक में मालिकों ने प्रत्येक मजदूर को 50/- अन्तरिम सहायता देना स्वीकार किया था तथा ट्रेड यूनियनों द्वारा पेश किए गये मांगपत्र पर शीघ्र ही वार्ता करने का वादा भी किया था. फिर भी प्रशासन बातचीत करने में देरी करता रहा और मजदूरों की समस्याओं पर एकतरफा निर्णय लेना भी शुरू कर दिया. उदाहरण के लिए मजदूरों के महंगाई भत्ते को मनमाने ढंग से जमा कर अन्तरिम सहायता का मजाक उड़ाया जा रहा है. सीटू बहुत पहले से ही संयुक्त कमेटी की बैठक करने के लिए बार बार मांग कर रही थी परन्तु प्रशासन देरी करने की नीति ही अपनाता रहा.

प्रशासन ने 19 मार्च को एक बैठक बुलाई परन्तु उसे भी अन्तिम समय में 22 मार्च के लिए स्थगित कर दिया जिससे संयुक्त कमेटी के सदस्यों को काफी परेशानी उठानी पड़ी. आश्चर्य ! कि 22 मार्च की इस बैठक को भी बिना उचित सूचना दिए हुए 7-8 अप्रैल के लिए स्थगित कर दिया है.

सीटू ने एच. एस. सी. एल. की इस नीति का जोरदार विरोध किया है और ट्रेड यूनियनों के साथ लापरवाही से पेश आने की भद्दी नीति को तुरन्त बन्द करने की मांग की है. सीटू ने अन्य ट्रेड यूनियनों से मांगों पर जोर देने के लिए संयुक्त आंदोलन छेड़ने की अपील की है जो कि मांगे हासिल करने का एकमात्र रास्ता है.

# कानपुर के बिस्कुट मजदूरों पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठी चार्ज

3 मार्च को अन्नपूर्णा बिस्कुट फैक्ट्री कानपुर के गेट पर मालिकों की गुप्त साजिश से पुलिस ने मजदूरों पर बर्बर लाठी चार्ज किया.

जब मालिकों और राज्य श्रम विभाग को बार-बार मांग-पत्र दिये जाने के बावजूद मांगें पूरी नहीं की गईं तब मजदूरों ने कानपुर बिस्कुट कर्मचारी यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में फैक्ट्री गेट से उप-श्रमायुक्त के कार्यालय तक जुलूस निकालने की योजना बनाई. जब अपना काम करने के बाद मजदूर फैक्ट्री गेट पर एकत्रित हो रहे थे तभी अचानक एक पुलिस दल ने वहां पहुंचकर अकारण लाठी वर्षा शुरू कर दी और लगभग 30 मजदूरों को घायल कर दिया. सहायक सचिव रामेश्वर प्रसाद मिश्र तथा सीटू नेता राजेंद्र सिंह तथा औरों को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद मालिकों ने मजदूरों पर और अत्याचार शुरू कर दिया. उन्होंने बहुत सारे मजदूरों को बर्खास्त कर दिया है तथा पुलिस की मदद से बाहरी लोगों से काम ले रहे हैं. फिर भी मजदूर बहादुरी से अपने कठिन संघर्ष को चला रहे हैं.

# राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

राजस्थान के साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारियों तथा अध्यापकों ने 18 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है. इस हड़ताल का आह्वान राजस्थान गवर्नमेन्ट इम्प्लाईज फेडरेशन के द्वारा वेतन ढांचे में सुधार के लिए वेरी आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने हेतु किया गया है. समाचारों के अनुसार हड़ताल पूर्ण रूप से सफल है, पूरे राज्य में सचिवालय, अदालतों, अस्पतालों, स्कूलों तथा अन्य जगहों पर सारा कामकाज ठप हो गया है.

उत्तर प्रदेश के 6 लाख सरकारी कर्मचारियों ने भी 22 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. सरकार ने आ. से. अ. के तहत हड़ताल पर पाबन्दी लगा दी है तथा 50 से भी अधिक कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है. इन दमनात्मक नीतियों के बावजूद 80% से भी अधिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं.

राजस्थान तथा उ० प्र० के हड़ताली कर्मचारियों का समर्थन करते हुए सीटू ने अपनी तमाम सम्बद्ध यूनियनों को मजदूरों के पक्ष में एकजुटता प्रकट करने का आह्वान किया है.

गुजरात से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वहां के 10 लाख कर्मचारियों ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय किया है.

सरकारों को अपने कर्मचारियों की बड़ी आर्थिक मांगों को स्वीकार न करने सम्बन्धी निर्देश देने के लिए निन्दा करती है. यही कारण है कि राज्य सरकारें कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को स्वीकार करने के बजाय उनके संघर्ष को दबाने के लिए एस्मा और एन. एस. ए. का प्रयोग कर रही हैं.

इस हड़ताल से जनता को होने वाली परेशानियों की पूरी जिम्मेदारी सीधे भारत सरकार पर आती है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के कारण दमन का रास्ता अपना रही है.

सीटू भारत सरकार से ऊंची कीमतों तथा लगातार खराब होती सेवा शर्तों के बोझ से परेशानियों के कारण संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर्मचारियों से टकराव का रास्ता छोड़कर सम्मानजनक समझौता करने के लिए समझौता वार्ता शुरू करने की मांग करती है जिससे जनता की कठिनाइयों को रोका जा सके. सीटू सरकार को चेतावनी देती है कि बिहार के सरकारी कर्मचारियों की तरह ये कर्मचारी भी अपने एकताबद्ध संघर्ष के द्वारा दमन का सामना करते हुए अपनी न्यायोचित मांगों को हासिल करने में सफल होंगे.

सीटू इस संघर्ष का पूरा-पूरा समर्थन करती है तथा उ० प्र० और राजस्थान में सीटू से सम्बद्ध तमाम यूनियनों, संघर्षरत सरकारी कर्मचारियों के प्रति एकजुटता जाहिर करने का निर्देश देती है. सीटू तमाम केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों तथा लोकतांत्रिक जनसंगठनों से, सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों को परास्त करने के लिए, संघर्ष के समर्थन में अपनी जोरदार आवाज उठाने की अपील करती हैं. □

## सीटू द्वारा बधाई

श्री पी राममूर्ति, संसद सदस्य तथा सीटू के महासचिव, ने 23 मार्च को निम्नांकित बयान जारी किया.

आ. से. अ. तथा रा. सु. अ. जैसे काले कानूनों की उपेक्षा करके बहुत दिनों से विचाराधीन अपनी न्यायोचित मांगों को हासिल करने हेतु हड़ताल करने के लिए मजबूर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सीटू बधाई देती है. सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी सदस्यों को एकताबद्ध कर सफल हड़ताल करना प्रसन्नता की बात है.

सीटू भारत सरकार की, सभी राज्य

## प्रशिक्षुओं के वजीफे में वृद्धि

दिनांक 25 जनवरी के भारत के असाधारण गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या डी जी इ टी 13-2-80 ए पी (जी. एस. आर. 24 ई. के द्वारा अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के तहत प्रशिक्षुओं के वजीफे की न्यूनतम दर इस प्रकार से बढ़ा दी गई है :—

| | |
|---|---|
| 1. ट्रेड अप्रेष्टिस (कारीगर प्रशिक्षु) | |
| प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष में | 230/- प्रति माह |
| ,, ,, द्वितीय ,, ,, | 260/- ,, ,, |
| ,, ,, तृतीय ,, ,, | 300/- ,, ,, |
| ,, ,, चतुर्थ ,, ,, | 350/- ,, ,, |
| 2. स्नातक अथवा तकनीकी प्रशिक्षु | |
| 1. इन्जीनियरिंग स्नातक (संस्था उपरान्त प्रशिक्षण के लिए) | 450/- प्रति माह |
| 2. सैण्डविच कोर्स स्टूडेण्ट्स (डिग्री संस्थानों से) | 320/- ,, ,, |
| 3. डिप्लोमा धारी (संस्था उपरान्त प्रशिक्षण हेतु) | 320/- ,, ,, |
| 4. सैण्डविच कोर्स स्टूडेण्टस (डिप्लोमा संस्थाओं से) | 250/- ,, ,, |

कारीगर प्रशिक्षुओं के लिए संशोधित दर केंद्रीय प्रशिक्षण परिषद की सर्वसम्मत्ति सिफारिशों के मुताबिक है, परंतु स्नातक अथवा तकनीकी प्रशिक्षुओं की दर बहुत ही कम है, यहां तक कि सरकार द्वारा शुरू-शुरू में प्रस्तावित दर से भी कम है. ये संशोधित दर 25 जनवरी 1982 से लागू है.

केंद्रीय प्रशिक्षण परिषद के सदस्य तथा सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने अपने 12 फरवरी के पत्र में महानिदेशक (रोजगार और प्रशिक्षण) श्रम मंत्रालय

शेष पृष्ठ दस पर

# 19 जनवरी के बाद दमन की बाढ़ : मजदूरों

जैसा कि पहले भी जानकारी दी जा चुकी है, 19 जनवरी की हड़ताल के बाद सरकार और मालिकों के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पीड़न और दमन की कार्यवाही की गई। सफल हढ़ताल से उत्साहित मजदूरों की एकजुट ताकत ने बहुत जगहों पर मालिकों को दमन की कार्यवाही वापस लेने पर मजबूर कर दिया. 23 फरवरी की देश व्यापी दमनविरोधी कार्यवाही एकजुट होकर दमन का प्रतिरोध करने की मजदूरों की आकांक्षाओं का प्रतीक है.

**हरयाणा**

सबसे ज्यादा दमन की कार्यवाही हरयांणा में की गई जहां स्वयं मुख्यमंत्री के आदेश से हांसी कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल तथा हरयाणा कंकास्ट के समस्त 1800 मलदूरों को गैरकानूनी रूप से वरखास्त कर दिया गया तथा मिल को वन्द कर दिया गया. मजदूरों को सभाओं में माइक का प्रयोग करने तक की इजाजत नहीं दी गई. स्थानीय एस. डी. एम. ने स्वयं टैन्ट हाउस जाकर मजदूरों को सभाओं के लिए शामियाना तथा दरी देने से मना किया. परन्तु बोलने के अधिकार पर इस प्रकार खुले आक्रमण के बावजूद मजदूरों के जबरदस्त संघर्ष ने मिलें खोलने और मजदूरों को वापस काम पर लेने के लिए प्रवन्धकों को मजबूर कर दिया. मजदूर 4 मार्च से काम पर जा चुके हैं. संसद सदस्य सुशील भट्टा चार्ज ने इस मामले को २५ फरवरी को लोकसभा मे उठाया तथा पी. राममूर्ति (संसद सदस्य) ने 3 मार्च को श्रम मंत्री से वार्ता किया.

सोंनीपत में गुप्ता बेकलाइट में तालाबन्दी कर दी गई. मालिको के गुन्डों ने मजदूरों और उनके परिवारों पर लाठियों तथा चाकुओं से आक्रमण किया. परन्तु मजदूरों ने निडर होकर संघर्ष किया और मालिक को तालाबंदी खतम करने के लिए मजबूर कर दिया. मंहगाई भत्ते के लिए संघर्ष जारी है.

**रेलवे**

रेलकर्मचारी संयुक्त समिति (पू. सी. रेलवे) ने रिपोर्ट दी है कि, सिलीगुड़ी शाखा सचिव, आलइन्डिया शंटिंग केबिन स्टाफ एसोसिएशन के क्षेत्रीय महासचिव, समिति के संयुक्त मंत्री तथा संगठन मंत्री आदि चार पदाधिकारियों को बरखास्त कर दिया गया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बरखास्तगी के खिलाफ स्थगन आदेश जारी कर दिया है. संघर्ष जारी है

एस. ई. रेलवे मेन्स युनियन की मिलाई मार्शलिंग यार्ड शाखा अध्यक्ष तथा टाटानगर के शाखासचिव को काले बिल्ले लगाने तथा जुलूस में हिल्सा लेने के लिए निलम्बित कर दिया गया है टाटानगर में 10 मजदूरों के खिलाफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्यों न उनके खिलाफ आवश्यक सेवा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय.

**बी ई एल बंगलौर**

भारत इलेक्ट्रानिक्स वर्कर्स युनियन (सीटू) के अध्यक्ष तथा संगठन मंत्री को आरोप पत्र दिए गये है तथा उनके दो इन्क्रीमेन्ट रोक दिए गये हैं. 17 अगस्त को आवश्यक सेवा अधिनियम की खिलाफत के समय भी उनके खिलफ यही दन्डात्मक कार्यवाहियां की गई थी. परन्तु तमाम सारी धमकियों के बावजूद 90% मजदूरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया तथा दन्डात्मक कार्यवाहियों की खिलाफ जोरदार संघर्ष चला रहे है.

**कोयला**

कोल इन्डिया ने मजदूरों के खिलाफ 8 दिन की वेतन कटौती तथा अन्य दन्डात्मक कर्यवाहियां की थी. मजदूरों ने लड़ाई लड़ी तथा नेशनल कोलआर्गनाइजेशन (गवर्नमेन्ट आफ-इन्डिया) इम्पलाइज एसोसिएशन (सीटू) द्वारा दी गई हड़ताल की नोटिस ने प्रबन्धकों को कार्यवाही वापस लेने के लिए मजवूर कर दिया.

**सुरक्षा**

इसापुर आर्डनेस फैक्ट्री, पश्चिम बंगाल के प्रबन्धको ने मजदूरों के खिलाफ सेवाभंग करने तथा अन्य प्रकार के दन्ड़ देने के आदेश दिए हैं.

**पान्डिचेरी**

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार स्टेट गवर्नमेन्ट इम्पलाईज एसोसिएशन के 1० पदाधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है.

तमिलनाडु कोआपरेटिव तथा अन्य जगहों के मजदूर 8 दिन की वेतन कटौती के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं.

**बालको, कोरबा**

भारत अल्युमिनियम, कोरबा (मध्य प्रदेश) के प्रबन्धको ने हड़ताल को गैरकानूनी घोसित करने के लिए अदालत का आदेश हासिल कर लिया तथा पोस्टर चिपकाने और दिवालों पर लिखने से मजदूरों को रोकने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल का इस्तेमाल किया. मजदूरों को 18 ता. की रात गैरकानूनी रुप से जबरदस्ती कारखाने में रोक रखा गया. नेताओ को 19 ता. की सुबह ही गिरफ्तत कर लिया गया तथा २५ ता. तक हिरासत में रखा गया. इन परिस्थितियों में केन्द्रीय मंत्री एन. डी. तिवारी २4 ता. को तीसरा दौर चालू करने के लिए बालको पहुंचे. मजदूरों ने विशाल प्रदर्शनों और भूख हड़तालो का आयोजन किया. अन्त में नेताओं को २५ ता. को छोड दिया गया, प्रबन्धको ने हड़ताल में हिस्सा लेने के लिए 8 दिन का वेतन काटने की नोटिस दी है.

**दवा उद्योग**

भारतीय दवा प्रतिनिधियों के महासंघ ने सूचित किया है कि हड़ताल में हिस्सा लेने के लिए उनके सदस्यों को कारण बताओ नोटिस दी जा रही है तथा अन्य प्रकार के दन्ड दिए जा रहे है.

**उत्तर प्रदेश**

मिर्जापुर से हिन्डालको वर्कर्स युनियन (सीटू) ने खबर दी है कि हिंन्डालको एल्युमिनियम कारपोरेशन के प्रशासन ने युनियन के

'सीटू मजदूर' परिशिष्ट वर्ष 4 अंक 4 अप्रैल 1982

# दसवां विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन

विश्व ट्रेड यूनियन संघ (डब्लू० एफ० टी०यू०) का दसवां सम्मेलन दि० 10 से 15 फरवरी तक हवाना में सम्पन्न हुआ. इस सम्मेलन का विशेष महत्व इस बात में है कि इसमें काफी बडे दायरे में प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. हिस्सा लेने वाले संगठनों में से केवल 20% संगठन ही डब्लू० एफ० टी० यू० से सम्बद्ध थे, बाकी सभी संगठन या तो किसी अन्य संगठन से जुड़े हुए थे अथवा स्वतंत्र. इस सम्मेलन में 27 करोड़ मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले 136 देशों के 351 ट्रेड यूनियन संगठनों के 800 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. यू० एन० ओ०, आइ० एल० ओ०, युनिसेफ, एफ० ए० ओ०, आई० सी० एफ० टी० यू०, डब्लू० सी० एल०, ओ० ए० यू० विश्व शान्ति परिषद, एवं अन्तर्राष्ट्रीय जनवादी महिला संघ के प्रतिनिधियों तथा अमेरिका से भी 56 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. इस प्रकार सम्मेलन ने पहली बार साम्राज्यवादी षड़यंत्रों के खिलाफ विश्वव्यापी संयुक्त आन्दोलन के लिए मेहनतकशों के बहुत बड़े हिस्से को शामिल किया.

इस सम्मेलन का पहली बार यूरोप से बाहर क्यूबा में किया जाना भी, क्यूबा में समाजवाद को खत्म करने, निकारागुआ के रास्ते को उलटने तथा अलसल्वाडोर और ग्वाटेमाला की जनता के फासीवादी गुटों के खिलाफ संघर्षों को नुकसान पहुंचाने के लिए चल रहे आक्रामक अमरीकी षड़यंत्रों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा.

सम्मेलन की कार्यवाही का संचालन 50 सदस्यीय अध्यक्षामण्डल ने किया. सीटू की तरफ से का० समर मुखर्जी ने सम्मेलन में हिस्सा लिया.

सम्मेलन ने पूंजीवादी विश्व के संकट और उसके परिणामस्वरूप अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा पैदा किए जा रहे युद्ध के खतरे पर विशेष रुप से विचार किया और शान्ति के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने के महत्वपूर्ण काम पर काफी जोर दिया. सम्मेलन ने दुनिया के अनेक हिस्से में फासीवादी तानाशाही के क्रूर अत्याचारों तथा विभिन्न देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा की जा रही छूट एवं वहां के पूंजीवादी गुटों द्वारा किए जा रहे दमन पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया और उस सबके खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग के आन्दोलन पर जोर दिया.

## उद्घाटन सत्र

विश्व ट्रेड यूनियन संघ (डब्लू० एफ० टी० यू०) के अध्यक्ष सन्दोर गैस्पर ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन ने शान्ति और मजदूर वर्ग के मूलभूत अधिकारों की रक्षा की लड़ाई के लिए काफी ताकत हासिल कर ली है. उन्होंने एक नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया।

उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए फीडेल कास्ट्रो ने मौजूदा विश्व स्थिति की गहराई से समीक्षा की और मजदूर वर्ग के काम की विस्तृत चर्चा की.

## मुख्य रिपोर्ट

सम्मेलन की मुख्य रिपोर्ट कार्यवाहक महासचिव इब्राहीम जकारिया के द्वारा प्रस्तुत की गई. रिपोर्ट का पहला हिस्सा सन 1978 में हुए पिछले सम्मेलन के निर्णयानुसार पिछले चार वर्षों में की गई संयुक्त कार्यवाहियों पर प्रकाश डालता है जैसे शान्ति, जीने का अधिकार, पूंजीवादी संकट के परिणामों की खिलाफत, बहुराष्ट्रीय इजारेदारी का विरोध, रोजगार की सुरक्षा, बेहतर सेवा शर्तों, ट्रेड यूनियन अधिकार, एकजुटता की कार्यवाहियां, आदि.

## नवें दशक की चुनौतियां

रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा-अमरीका द्वारा की जा रही युद्ध की तैयारियों, उनके द्वारा सम्पूर्ण विश्व को आणविक युद्ध की चपेट में लेने के लिए विज्ञान और तकनीक की आश्चर्यजनक प्रगति के उपयोग में लाने, हथियार उद्योग की मुनाफाखोरी, काम करने और जीने के अधिकार सम्बन्धी मूलभूत सवाल उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद, नस्लवाद तथा फासीवाद द्वारा करोड़ों लोगों के लिए मानवीय अधिकारों से इंकार आदि-नवे दशक की तमाम चुनौतियों पर प्रकाश डालता है. तीसरे हिस्से में विश्व ट्रेड यूनियन आन्दोलन को और भी मजबूत बनाने का आह्वान किया गया है तथा अन्तिम हिस्से में विश्व ट्रेड यूनियन संघ का मजदूर वर्ग की और दृढ़ता के साथ सेवा करने के लिए अह्वान किया गया है.

मुख्य दस्तावेज "ट्रेड यूनियनें तथा नवें दशक की चुनौतियां" शान्ति और निशस्त्रीकरण, बहुराष्ट्रीय निगम, तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार पत्र के मसौदे आदि पर कई आयोगों ने काम किया.

## अमरीका-विश्व प्रतिक्रियावाद का पुलिस

पूंजीवादी देशों से आए प्रतिनिधियों ने गहरे संकट और फलस्वरूप मजदूर वर्ग पर हो रहे आक्रमण पर प्रकाश डाला. लैटिन अमरीका के प्रतिनिधियों ने फासीवादी जबरजस्त पर तथा

[शेष पृष्ठ सात पर]

# विकास के पूंजीवादी रास्ते का नाश हो

*(दसवीं विश्व ट्रेड यूनियन कांग्रेस में का० समर मुखर्जी के भाषण का संक्षिप्त रूप)*

प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए समर मुखर्जी ने सम्पूर्ण विश्व को आणविक विध्वंस के कगार पर ला खड़ा करने में अमरीका के योगदान पर अपना विचार रखा. उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर न्युट्रान बमों के निर्माण तथा रासायनिक युद्ध को तेज करने सम्बन्धी रीगन प्रशासन के निर्णयों ने मानव जाति के सम्पूर्ण विनाश का खतरा पैदा कर दिया है.

यह प्रसन्नता का विषय है कि ब्रिटेन और युरोप के मजदूर वर्ग ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है. अमरीका में भी विरोध प्रदर्शन शुरु हो चुके हैं. यह इस बात का संकेत है कि मजदूर वर्ग और शान्तिप्रिय जनता इन युद्धबाजों की रोकथाम कर सकती है.

जहां तक भारतीय जनता का सवाल है, अमरीकी प्रशासन द्वारा पाकिस्तान के सैनिक शासकों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने के निर्णय से यह खतरा अब हमारी सीमाओं तक पहुंच चुका है. इसी प्रकार समुद्रतटीय देशों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद हिन्दमहासागर स्थित डियागो गार्सिया में सैनिक अड्डा कायम करने के अमरीकी निर्णय ने इस खतरे को और भी गहरा कर दिया है. हमें यकीन है कि भारतीय मजदूर वर्ग पाकिस्तानी मजदूर वर्ग के निकटतम सहयोग से एशियाइयों को आपस में लड़ाने की इस अमरीकी साजिश को विफल करने में सफल होगा.

## विदेशी कर्ज पर भारत की निर्भरता

मुख्य दस्तावेज के मसौदे में ठीक ही कहा गया है कि पूंजीवादी दुनियां गहरे आर्थिक संकट में फंसी हुई हैं. भारत भी इसका अपवाद नहीं है. भारतवर्ष में मुद्रास्फीति पिछले एक दशक से लगातार बढ़ती रही है और अब यह स्थाई विशेषता बन चुकी है. क्योंकि भारतीय अर्थ व्यवस्था पश्चिमी पूंजीवादी देशों से जुड़ी हुई है.

छठी योजना में विदेशी सहायता का उपयोग 13000 से 15000 करोड़ के बीच होगा. निर्यात से होने वाली आमदनी में तेज बढ़त के बावजूद निर्यात के प्रतिशत के हिसाब से कर्ज-अदायगी का बोझ 27% की ऊंचाई तक पहुंच गया. विदेशी कर्ज की अदायगी के लिए देश पर और अधिक निर्यात थोप दिया गया है.

## विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के आदेश

भारत की अर्थव्यवस्था में विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का हस्तक्षेप और सुस्पष्ट हो रहा है. विश्व बैंक खाद्यान्नों पर दी जा रही मदद को खत्म करने की मांग करता रहा है. विश्व बैंक आयात को कम करके आत्मनिर्भर बनने की नीति को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा निर्यात बढ़ाने की नीति अपनाने के लिए दबाब डालता रहा है जिसका अर्थ है वस्तुओं को देशी बाजार से हटाकर विदेशी बाजार की तरफ ले जाना. इसके साथ यह बहुराष्ट्रीय उद्यमों और विदेशी पूंजी की घुसपैठ के लिए आसान शर्तों के लिए भी दबाव डालता रहा है. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने भारत द्वारा 5000 करोड़ रुपये के कर्ज के लिए दिए गये आवेदन पर अपनी वार्ता में इसी तरह की कठोर शर्तें लगाई हैं. यह बजट कर प्रस्तावों में हस्नक्षेप तथा भुगतान संतुलन की स्थिति पर नियंत्रण की मांग कर रहा है. इन दबावों के पपिणाम-स्वरूप सरकार ने जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ लाद दिए हैं.

## बहुराष्ट्रीय निगमों की घुसपैठ

भारत सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की बेहतर सुविधाओं की मांग को भी स्वीकार कर लिया है. विदेशी सहयोग स्वीकृति तथा विदेशी पूंजी की जरूरत वाले उद्यमों की स्वीकृति 1979 की तुलना में 1980 तक दूनी हो चुकी है. जैसा कि पिछले वर्ष में था, वैसे इस वर्ष भी सहयोग स्वीकृति का अधिकांश जर्मनी, ब्रिटेन और अमरीका के साथ है. यह सब उसी समय किया गया जब की सम्पूर्ण तीसरी दुनियां इन एजेंसियों से स्वतंत्रता और जनतंत्र को खतरा महसूस कर रही थी.

भारत में इन्हें काफी रियायतें दी गई जबकि दवा और अन्य बहुराष्ट्रीय उद्योग अमानत में उनके हिस्से को कम करने सम्बन्धी सरकार के निर्देशों का लगातार उल्लंघन करती रही हैं. इन उद्योगों ने विकसित तकनीक लागू करने के बहाने विदेशी मुद्रा अधिनियम को तोड़ने और 74% हिस्सा लगाने की आजादी हासिल कर ली है. ये इतने शक्तिशाली हैं कि इन्दिरा सरकार इन उद्यमों का राष्ट्रीयकरण करने सबन्धी हाथी कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का साहस नहीं कर सकी. सीटू इन कम्पनियों के घृणित कारनामों के खिलाफ लगातार संघर्ष करती रही है. सीटू ने ए. यू. सी. सी. टी. यू. के निमंत्रण पर 4-5 मई 1981 को मास्को में हुए सम्मेलन में हिस्सा लिया. भारतवर्ष में दवा उद्योग में बहुराष्ट्रीय निगमों के खिलाफ एक सम्मेलन तथा गोष्ठी का आयोजन क्रमशः अप्रैल और नवम्बर 81 में दिल्ली में किया गया.

## औद्योगिक बीमारी

उद्योगों में बीमारी बढ़रही है.भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 1979 के अन्त में 345 बड़ी औद्योगिक इकाइयां बीमार थी जिनमें बैंक की कुल 1101.2 करोड पूंजी लगी हुई थी, उन्हे हिरासत में ले लिया गया. यह सार्वजनिक क्षेत्र के कुल पूंजी निवेश से ज्यादा है. छोटे आकार के उद्योगो में बीमार इकाइयों की संख्या 20326 थी.

## बढ़ती कंगाली

ज्यादा से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे ढ़केले जा रहे है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 48% अर्थात 30 करोड़ देशवासी गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे है. यह कम करके दिखाया गया है क्यो कि यह संख्या 1973-74 में ही 61% तक पहुंच चुकी थी.

## बेरोजगारी

पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 74-75 तथा 80-81 के बीच 10.6% वार्षिक की रफ्तार से बढ़ी है तथा 79-80 और 80-81 के बीच वृद्धि की रफ्तार 13.3% रही है.

## मकान की समस्या

शहरों तथा गावों में गृहनिर्माण में लगातार गिरावट से रिहाइश की समस्या और गहरी हो गई है. कुल शहरी आबादी का पांचवा हिस्सा गन्दी बस्तियों में रहता है. 1985 तक आवास के लिए जरुरत मन्दों की संख्या 3 करोड 70 लाख तक पहुंच जाने का अनुमान है. देहाती इलाकों में आवास की सुविधा चाहने वाले परिवारों की संख्या एक करोड 45 लाख तक हो जायेगी.

## जनता की लूट

भारत सरकार अपनी, वेतन जाम की नीति, मंहगाई भत्ते को अनिवार्य रूप से जमा रखने के प्रस्ताव, किसानों को वाजिब कीमते देने के विरोध, खेतिहर मजदूरों को उचित वेतन देने की गारंटी से इंकार, तथाकथित उच्च वेतन भोगियों पर आक्रमण, हड़तालों पर पाबन्दी आदि नीतियों के द्वारा संकट के बोझ को आम जनता के उपर लाद देना चाहती है, जब कि दूसरी तरफ भूस्वामियों, इजारेदारों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा बड़े व्यापारियों को रियायते दे रही है.

## सामाजिक सुरक्षा

सीटू सामाजिक सुरक्षा की घोषणा में सन्निहित सूत्रों का स्वागत करती है. फिरभी भारत में स्थिति भिन्न है. सामाजिक सुरक्षा प्रत्येक क्षेत्र में होनी चाहिए जैसे; (1) स्वास्थ्य सुरक्षा, (2) बीमारी (3) प्रसवकालीन सुविधा (4) काम कर सकने में असमर्थता के लिए सुविधा, (5) वृद्धावस्था, (6) उत्तर-जीविता, (7) सेवाकालीन चोट और रुग्णता, (8) बेरोजगारी, (9) परिवार आदि. परन्तु ई. एस. आई. ऐक्ट में सामाजिक सुरक्षा के बहुत ही थोड़े क्षेत्रो का प्रावधान है और वह भी बहुत कन्जूसी के साथ. प्रति व्यक्ति वार्षिक खर्च केवल 120 रु रखा गया है. अपर्याप्त चिकित्सा सहायता के लिए मजदूरों को अपनी कठिन कमाई से अदा करने के लिए मजबूर किया जाता है जो कि स्वयं उनके और उनके परिवार के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ही कम है. अस्पताल की सुविधा देने का वादा एक और ढोंग है क्योंकि अस्पतालों में 1500 व्यक्तियों पर एक बेड की व्यवस्था है.

मजदूरों के स्वास्थ्य की यह अनुचित उपेक्षा धन की कमी के कारण नहीं की जा रही है. ई. एस. आई. निगम ने 30 करोड़ रुपया एकत्रित कर रखे हैं. एकत्रित धन को काम में लाने से इंकार करना, अदायगी न करने वाले मालिकों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने से इंनकार करना तथा हड़ताल के दौरान समस्त सुविधाओं कों वापस लेने का प्रस्ताव आदि सभी सुविधाओं को छीन लेने की खतरनाक नीति के हिस्से हैं जब कि सरकार मजदूरों से वसूल की गई रकम को उपयोग कर रही है.

## नवें दशक की चुनौतियां

अतः विश्व मजदूर वर्ग के समक्ष विकसित पूंजीवादी देशों—धनी उत्तर—द्वारा सम्पूर्ण दुनिया पर हावी होने की कोशिशों के खिलाफ संघर्ष करने का कदम नवें दशक की चुनौतियों में शामिल है.

अतः सीटू का मत है कि भूख के खिलाफ अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी शक्तियों के बिश्व पर हावी होने के खिलाफ तथा अपने जीवनस्तर को बेहतर बनाने के लिए विकासमान देशो के मजदूर वर्ग के संघर्षों के समर्थन में विश्व ट्रेड यूनियन आन्दोलन को जोरदार आवाज उठानी चाहिए. नवे दशक की चुनौतियां भारतीय मजदूर वर्ग से भी मांग करती हैं कि वेभारत सरकार को मजदूर एवं लोकतंत्र- विरोधी नीतियों के बदलने के लिए मजबूर करने हेतु जनता को लामबन्द करें. सीटू देश में संयुक्त मजदूर आन्दोलन का निर्माण करने के लिए उचित प्रयत्न करती रही है. 4 जून 1981 को बंबई में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 8 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों तथा 40 राष्ट्रीय महासंघों के 4000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. बढ़ती कीमतों तथा सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का कार्यक्रम तैयार किया गया. इन तमाम ट्रेड यूनियन संगठनों तथा संसद में विरोधी राजनैतिक दलों के विरोध के बावजूद भारत सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के माध्यम से किसी भी उद्योग अथवा संस्था में किसी हड़ताल को गैर कानूनी घोषित करने का अधिकार हासिल कर लिया है. भारत सरकार की इन तमाम नीतियों के खिलाफ सम्पूर्ण देश के मजदूरों ने 19 जनवरी 1982 को एक दिन की आम हड़ताल की. हड़ताल से पहले और बाद में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और दमन किया गया. इस बात की विशेष रूप से जिकर करने की जरुरत है कि भारत वर्ष में ट्रेड यूनियन अधिकारों का हनन हो रहा है, तथा संगठन बनाने की आजादी और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके विषय में संयुक्त रूप से एक शिकायत अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन को दी जा चुकी है.

हम इस बात की घोषणा करते हैं कि नवें दशक की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत का मजदूर वर्ग सरकार और शोषक वर्गों के दमन का सामना करते हुए विश्व मजदूर वर्ग के साथ आगे बढ़ता जाएगा. हमें यकीन है कि सरकार की इजारेदार समर्थक, मजदूर- विरोधी नीतियों तथा तानाशाही के खिलाफ हमारे संघर्ष में विश्व मजदूर आन्दोलन अपनी एकजुटता जाहिर करेगा और हमारा साथ देगा.

तमाम दुनिया के मजदूरों की एकता जिन्दाबाद.

# सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के झंडे को ऊंचा रखो

*(विश्व ट्रेड यूनियन संघ की दसवीं कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में फीडेल कास्ट्रो के भाषण का संक्षिप्त रूप)*

कांग्रेस के व्यापक चरित्र को विशेष महत्वपूर्ण बताते हुए फीडेल कास्ट्रो ने कहा कि इस कांग्रेस के लिए प्रदर्शित उत्सुकता और बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी, सर्वाधिक ताकत के साथ प्रदर्शित दुनिया के तमाम मजदूरों के हितों की एकता की पूर्ण अभिव्यक्ति है. हम कह सकते हैं कि यह कांग्रेस, जिसकी शुरुआत आज हम बड़ी प्रसन्नता के साथ कर रहे हैं, तमाम दुनिया के संगठित मजदूरों के जबरदस्त बहुमत की कांग्रेस है.

यह पहला मौका है जब इस तरह की कांग्रेस युरोप के बाहर हो रही है और वह भी क्यूबा में, जो रोज रोज की धमकियों, हर तरह के दुष्प्रचार और बड़ी आर्थिक नाकेबन्दी के बीच अपने आर्थिक विकास के लिए संघर्ष कर रहा है. क्यूबा को शेष दुनिया की जनता से काटने की उसके दुश्मनों की नाकामयाब कोशिशों के संदर्भ में वहां इस कांग्रेस के आयोजन को फिडेल ने अपने देश के प्रति गहरी एकजुटता के प्रदर्शन का नाम दिया और इसके लिए क्यूबाई जनता तथा सरकार की तरफ से आभार प्रकट किया.

## मुख्य अन्तर्विरोध

इस हाल में भिन्न-भिन्न राजनैतिक, दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों के लोग उपस्थित हैं, जिसकी वास्तव में हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं. परिस्थितियों और विचारों का बहुत बड़ा दायरा है.

क्या इन परिस्थितियों में हम एक सामान्य भाषा हासिल कर सकते हैं ? हम विश्वास करते हैं कि यह सम्भव है, और आवश्यक है तथा इससे भी अधिक अपरिहार्य है. बहुत सारे अन्तर्विरोध हो सकते हैं, और कभी-कभी गम्भीर भी हो सकते हैं. परन्तु हम सब का यहां एकत्रित होना इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे इन अन्तर्विरोधों से कहीं गहरा और गम्भीर अन्तर्विरोध भी है, उनके साथ अन्तर्विरोध जो सम्पूर्ण मानव जाति को युद्ध के रास्ते पर खींच ले जाना चाहते हैं, जो खतरनाक स्थिति से गुजर रही विश्व अर्थव्यवस्था से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं तथा संकट के बोझ को मजदूरों के ऊपर डाल देना चाहते हैं. इस कठिन और खतरनाक मौके पर हमें उन सवालों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें एक करते हैं, न कि उन सवालों पर जो हमें अलग करते हैं. हमें पूरा विश्वास है कि विश्व ट्रेड यूनियन आन्दोलन, हममें से किसी को भी अपने खयालात बदलने के लिए मजबूर किए बिना, सारी दुनिया के मजदूरों और आम जनता के हितों की रक्षा के महान उद्देश्यों को आगे रखते हुए आपसी बातचीत, एकता पैदा करने तथा साझा कार्यवाही के लिए उचित कदम उठाने हेतु अग्रसर हो सकता है. इसका मतलब है सारी जनता के जीवित रहने, काम करने, भोजन प्राप्त करने, तथा सुरक्षित सम्मानित एवं न्यायपूर्ण जीवन के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होना.

## शान्ति के लिए संघर्ष

इस समय हमारे सामने, शान्ति के लिए संघर्ष तथा आणविक विध्वंस से सम्पूर्ण मानवता के विनाश को रोकना, निःसन्देह रूप से सबसे जरूरी काम है. परन्तु इस संघर्ष को, विकास की समस्याओं तथा अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण जीवन के लिए चल रहे शोषित जनता के संघर्षों से अलग नहीं किया जा सकता है. हम भिन्न नजर से नहीं देख सकते हैं और न ही विभिन्न देशों की परिस्थितिगत असमानता की उपेक्षा कर सकते हैं. मजदूर केवल जिन्दा रहने के लिए ही नहीं सोचता बल्कि जीवन के हालात के विषय में भी गहरी रुचि रखता है. अतः यह सर्वथा तर्कसंगत है कि तमाम दुनिया के मेहनतकश शान्ति के लिए संघर्ष तथा तनाव को कम करने में अपनी रुचि दिखाएं. परन्तु दुनिया के बहुत से इलाकों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे मजदूरों की है जिनका जीवन इतना अनिश्चित, जीवननिर्वाह इतना कठिन और सम्भावनाएं इतनी हताशापूर्ण हैं कि उनके लिए शान्ति के लिए संघर्ष के नारे का कोई मतलब नहीं होता. यदि सचमुच में हम विश्वव्यापी मजदूर आंदोलन संगठित करना चाहते हैं तो शान्ति की सुरक्षा तथा मजदूरों की आवश्यक तात्कालिक मांगों, दोनों के लिए ही एक साथ संघर्ष करना होगा.

## युद्ध का खतरा

संसार के जिम्मेदार राजनीतिक नेता स्वीकार करते हैं कि आज लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे अधिक जटिल और गम्भीर परिस्थितियों में रह रहे हैं. आज सम्पूर्ण मानवता, श्रम की महान रचनाओं तथा ज्ञान विज्ञान की धरोहरों को सदा सदा के लिए समाप्त करने में केवल कुछ ही क्षणों की जरूरत होगी. इस बढ़ते हुए खतरे के खिलाफ, खड़े होने और संघर्ष करने की पहली शर्त है कि हम इसे पहचानें.

## बढ़ती शस्त्रों की दौड़

अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि की पूरी जिम्मेदारी अमरीका प्रशासन और उसके कुछ सहयोगियों पर है. वे सोवियत दखलंदाजी या विस्तारवाद की थोथी दलील देकर क्रान्तिकारी राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों, यहां तक कि हर प्रगतिशील प्रकिया को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं. वे रणनीतिक शक्ति संतुलन को बदलने की तथा सामरिक बढ़त हासिल करने की, और इस बढ़त के जरिये ब्लैकमेल तथा दबाव के द्वारा अपने राजनैतिक आदेश थोपने की नामुमकिन कोशिश कर रहे हैं. अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने इतिहास की सबसे भयानक "हथियारों

की दौड़" छेड़ दी है. कोई भी प्रचार तथा तथ्यों की तोड़ मरोड़ इस सच्चाई को छिपा नहीं सकती है. इन घोर प्रतिक्रियावादी और आक्रामक नीतियों के पीछे, इन नीतियों से प्रमुख रुप से फायदा उठाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गठजोड़ के हितों और मुनाफों का हाथ है. इस नीति से अगर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और खासकर सैनिक औद्योगिक गठजोड़ के हित पूरे हो रहे हैं और उनके मुनाफे दुगने चौगने हो रहे हैं तो मजदूरों की बहुत बड़ी जमात को जीवन स्तर में गिरावट, बेकारी, मंहगाई, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं में कटौती अस्थिरता और गरीबी आदि की भयानक तबाही का सामना करना पड़ रहा है. साम्राज्यवाद की नीतियों ने विश्व शान्ति के लिए गम्भीर खतरा पैदा कर दिया है. साम्राजियों की इस कोशिश के खिलाफ लाखों लाख मजदूरों कर्मचारियों, बुद्धिजीवियों और छात्रों, पुरुषों और महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों तथा नौजवानों आदि के जुझारु प्रदर्शन हुए हैं. इतने विशाल और जुझारु प्रदर्शन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार हुए हैं.

## सैन्य-वृद्धि

अमरीका के पास इस समय नाभिकीय हथियारों के प्रक्षेपण की 2112 इकाइयां हैं जिनमें अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ने के प्लेटफार्म, जंगी विमान और पनडुब्बियां शामिल हैं. भीषण विध्वंस क्षमता के अलावा अमरीका के पास 4 लाख की सेना है, 200 मिसाइल वाहक हैं, जो शस्त्रों में फिट किए जा सकते हैं, 11000 से ऊपर टैंक हैं, आणविक तोपों समेत 12000 जमीन से मार करने वाले तोपखाने हैं, तरह तरह की 20 हजार वायु सेना इकाइयां हैं, और 848 नौसैनिक इकाइयां हैं जिनमें 79 नाभिकीय पनडुब्बियां और 20 विमानवाहक पोत शामिल हैं. दुनिया भर में उसके 300 से ऊपर बड़े फौजी अड्डे हैं और 5 लाख से ज्यादा सैनिक हैं जो बराबर दूसरे देशों में तैनात रहते हैं.

मौजूदा नाभिकीय अस्त्रों की विस्फोट क्षमता हिरोशिमा के बम से लगभग 15 लाख गुना ज्यादा है.

आधुनिकतम और खतरनाक हथियारों का फैलाव खतरे को बढ़ा रहा है तथा कभी भी गैरजिम्मेदाराना एवं विवेकहीन कार्यवाहियों से नाभिकीय विध्वंस की सम्भावनाएं बढ़ गयी है.

## सैनिक बजट

अर्थशास्त्रीय भाषा में, हथियारों का जखीरा खड़ा करने की उन्मादपूर्ण अमरीकी सनक के परिणामस्वरूप 1986 में सैनिक बजट पर कुल 373 अरब डालर खर्च किए जाने की सम्भावना है जो उस वर्ष के कुल अमरीकी बजट का 36% होगा. 1982-86 के बीच अमरीका अपनी फौजी तैयारियों पर 1500 अरब डालर खर्च करने जा रहा है.

## साधनों की बर्बादी

अमरीका द्वारा छेड़ी गई इस हथियारों की दौड़ में साधनों की भयानक बर्बादी हो रही है जब दुनियां आज पिछले 50 वर्षों के गम्भीरतम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है.

यह सोचकर मानव मस्तिष्क गुस्से से भर जाता है कि यदि सैनिक बजट पर खर्च किये जा रहे साधनों का एक हिस्सा भी जनता की भलाई और प्रगति के लिए लगा दिया जाय तो तमाम दुनिया की आबादी को कष्ट में डालने वाली कठिन समस्याओं, जैसे सांस्कृतिक पिछड़ापन, स्वास्थ्य सुरक्षा की अनुपयुक्तता, आवास तथा बेकारी आदि को बहुत कुछ हद तक खत्म किया जा रहा है.

## मानव जाति पर प्रभाव

इन सब भीमकाय खर्चों से आखिर दुनियां की तमाम जनता को क्या हासिल हो रहा है? दुनियां भर के वैज्ञानिकों का गरीब 25% हिस्सा सैनिक कार्रवाइयों में लगा हुआ है. अनुमान है कि वैज्ञानिक शोध पर होने वाले कुल खर्च का 60 फीसदी हिस्सा सिर्फ सैनिक कार्यक्रमों पर जाता है. सैनिक कार्यों से सम्बद्ध शोध योजनाएं दुनियां भर की स्वास्थ्य योजनाओं की पांच गुनी बैठेंगी. गरीबी, भूख, अज्ञानता, कंगाली और साधनों की कमी के शिकार तीसरी दुनियां के देशों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? एशिया अफ्रीका और लैटिन अमरीका के देश अपने कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 5.9 फीसदी हिस्सा सेना तथा हथियारों पर खर्च कर रहे हैं जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्रमशः 1 फीसदी और 2.8 फीसदी हिस्सा ही खर्च कर रहे हैं.

एक आधुनिक टैंक पर होनेवाले खर्च से अविकसित देशों के 30 हजार बच्चों के लिए स्कूल के 1000 कमरों का निर्माण किया जा सकता है. एक ड्राइडेंट नाभिकीय पनडुब्बी पर होनेवाले खर्च से—1990 तक अमरीका ऐसी 13 पनडुब्बियां बनाने जा रहा है—अविकसित देशों के 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को एक साल की स्कूली शिक्षा दी जा सकती है तथा 20 लाख लोगों की रिहाइश के लिए 4 लाख मकानों का निर्माण किया जा सकता है. बेहिसाब साधनों की बर्बादी के इस बेहूदेपन के अनगिनत उदाहरण दिये जा सकते हैं.

## झूठे प्रचार

हथियारों की इस दौड़ का बुरा प्रभाव पूंजीवादी दुनिया और समाजवादी दुनिया दोनों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है. परंतु इसके लिए दोनों ही को दोषी ठहराने की कोशिश करना सच्चाई को झुठलाना है. हमें पूरी ईमानदारी से इस वस्तुगत तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि पिछले 40 वर्षों में नये तरह के रणनीतिक हथियारों के विकास और उत्पादन में समाजवादी देशों ने कभी पहल नहीं की है. इसके विपरीत दुश्मन की आक्रामक नीतियों और धमकियों के सामने मजबूर होकर अपनी संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा के लिए ही समाजवादी देशों को शस्त्र का बोझ उठाना पड़ रहा है.

## खतरा किससे है

हमें स्वयं से यह सवाल पूछना चाहिए की, "क्या अमरीका को किसी से खतरा पैदा हो गया है," "क्या कोई ताकत उस पर आक्रमण की तैयारी कर रही है" "क्या अमरीका द्वारा सैनिक खर्चों पर की जा रही बेतहाशा वृद्धि को राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे के नाम पर न्यायोचित करार दिया जा सकता है". यकीनन इसका

उत्तर है, "नहीं". इस सबकी एकमात्र व्याख्या यही हो सकती है कि घोर दक्षिणपंथी दल के अमरीका की विश्व प्रतिक्रियावाद के पुलिसिए की भूमिका को आगे बढ़ाने और दुनियाभर के मजदूरों तथा जनता के संघर्षों को रोकने की अपनी कोशिश में कुछ भी करने के लिए तैयार हैं.

## मजदूरों पर प्रभाव

गहरे संकट के दौर से गुजर रही पूंजीवादी व्यवस्था को जिसके परिणामों का दुस्प्रभाव सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर तथा विशेष रूप से मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है, देखते हुए यह हथियारों की दौड़ असह्य हो जाती है.

वर्तमान संकट के दौर में भी इजारेदारियां पहले की ही तरह, उत्पादन में कटौती, निवेश को कम करने, कारखानों की क्षमता का पूरा-पूरा इस्तेमाल न करने तथा करोड़ों मजदूरों को बेरोजगार बनाने का काम कर रही हैं. वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रांति के फलों पर काबिज इजारेदार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, और नये-नये तरीकों से मजदूरों के शोषण को तेज करने और उनकी काम की स्थितियों को बद से बदतर बनाने, के लिए संकट का पूरा-पूरा फायदा उठा रही हैं.

## बेरोजगारी

पिछले 50 वर्षों में बेरोजगारी अभूतपूर्व सीमा तक पहुंच चुकी है. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन से संबद्ध विकसित पूंजीवादी देशों में बेरोजगारों की संख्या सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1981 में 2 करोड़ 50 लाख तक पहुंच चुकी है जो कि 1980 के आंकड़ों से 40 लाख तथा 74-75 के आंकड़ों से 1 करोड़ अधिक है. 1982 तक इस संख्या के 2 करोड़ 80 लाख तक पहुंच जाने की संभावना है. ऊपर से ये आंकड़े झूठे भी हैं, इनसे बेरोजगारी की सही स्थिति का पता नहीं चलता क्योंकि प्रभावित देश विभिन्न छलपूर्ण तरीकों से सही स्थिति को छिपाने की कोशिश करते हैं.

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के अनुसार 1980 में तीसरी दुनिया के देशों में बेरोजगारों तथा अंशकालिक रोजगार पानेवालों की संख्या 45 करोड़ 50 लाख थी जोकि कुल काम कर सकने योग्य आबादी का 43 प्रतिशत है. तबसे स्थिति लगातार खराब ही हुई है.

## औरतें सर्वाधिक प्रभावित

संकट के इस दौर में बेरोजगारी की दृष्टि तथा शोषकों के मजदूर-विरोधी हमले औरतों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं. समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को बहुत से पूंजीवादी देशों ने स्वीकार किया है परंतु फिर भी पुरुषों और महिलाओं के वेतनों में 20 से लेकर 50 प्रतिशत का अंतर बरकरार है.

## तीसरी दुनिया के देश

इस पूंजीवादी संकट का प्रभाव, अल्पविकसित देशों पर, उनकी उत्पादक शक्तियों के घटिया विकास तथा आर्थिक संरचना के गलत गठन के कारण, और भी गहराई से पड़ रहा है.

आंकड़ों से ज्ञात होता है कि अल्पविकसित देशों का कुल राष्ट्रीय उत्पादन 1979 के 4.8% से 1980 में 3.8% और 81 में 3.2% तक कम हुआ है. अल्पविकसित दुनिया के सबसे कम आमदनी वाले देशों की वार्षिक वृद्धि दर सातवें दशक में केवल 1.8% तथा आठवें में 0.8% रही.

तेल को छोड़कर बाकी विश्व निर्यात में अल्पविकसित देशों का हिस्सा 1950 के 25% की तुलना में 1980 में 12% से भी कम हो गया. मूल उत्पादन और निर्मित वस्तुओं के बीच व्यापारिक सम्बन्धों में लगातार गिरावट ने, जोकि तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण और भी तेज हो गई है, तेल आयात करने वाले अल्पविकसित देशों के भुगतान घाटे को और भी गहरा कर दिया है जो कि 1980 में 53 अरब डालर था.

आर्थिक दृष्टि से इन परिस्थितियों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हुआ है. अल्पविकसित देशों के उपर भारी कर्जों का बोझ. अनुमानतः तथाकथित तीसरी दुनिया के देशों का विदेशी कर्ज 1981 तक 524 अरब डालर तक पहुंच चुका है. कर्जों की ब्याज की लगातार बढ़ रही दर से अदायगी के लिए और भी कर्ज और इस तरह यह चक्र चलता ही रहेगा. वास्तव में अल्पविकसित देशों का बहुत बड़ा हिस्सा कभी भी इस भारी कर्ज के बोझ से मुक्त नहीं हो पाएगा. यह ऐसी स्थिति है जिसे कुछ ही शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, भूख, अज्ञानता, कंगाली गरीबी, बेरोजगारी, अवसर की कमी, सुरक्षा का अभाव, तथा हताशा और गैरबराबरी आदि-आदि.

युद्ध, खूनखराबा, सामाजिक अन्याय, वर्गों तथा राज्य के शोषण आदि उपनिवेशवादी तथा नवउपनिवेशवादी परम्पराओं की वसीयत से ग्रस्त साम्राज्यवाद की स्वार्थी, जंगबाज और आक्रामक नीतियां ही इन खतरनाक परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं.

## मजदूरवर्ग की भूमिका

मानव जाति इन समस्याओं का समाधान कर सकती है और उसे ऐसा करना ही होगा. यदि हम दृढ़ता से इस बात में विश्वास नहीं करते हैं तो यह तमाम दुनियां की शोषित पीड़ित जनता की संघर्ष और प्रगति कर सकने की अकूट क्षमताओं को कम करके आंकना होगा. इस संघर्ष में मजदूर वर्ग को नेतृत्वकारी भूमिका निभानी होगी. समाज के सबसे क्रांतिकारी वर्ग होने के नाते, अन्याय पर आधारित इस समाज व्यवस्था को बदलने के ऐतिहासिक काम में मजदूर वर्ग ही अग्रणी भूमिका निभा सकता है.

## सभी बाधाओं को तोड़ दो

एक शताब्दी से भी अधिक समय से साम्राज्यवादी और शोषक मजदूर वर्ग के संघर्षों को बांटने, विरोध करने और कमजोर करने की नीति अपनाते रहे हैं. लगातार छोटी होती हुई और अन्तःसम्बद्ध आज की दुनिया में, समस्याओं की विश्वव्यापी प्रकृति और हमारे आर्थिक जीवन में इजारेदारियों की मौजूदगी ने तमाम मजदूर वर्ग के हितों की एकरूपता को इतना बढ़ा दिया है कि आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ एक तरह की कार्यवाही की जरूरत महसूस की जाने लगी है.

आज की दुनिया में ऐसे लोग और ऐसे विषय नहीं रहे जो अपनी ही चारदीवारियों तक सीमित हों. बहुराष्ट्रीय गठजोड़ की

गतिविधियां इसका प्रमाण हैं, जो कि तमाम उद्योगों और संयंत्रों को निम्न जीवन स्तर वाले देशों में स्थानान्तारित करके विभिन्न देशों के मजदूरों में प्रतिद्वन्द्विता पैदा कर रहे हैं, अपने मुनाफों को दुगना चौगुना कर रहे हैं तथा प्रायः दमनकारी और खूनी सरकारों का सहारा लेकर मजदूर वर्ग की न्यायोचित मांगों को देने से इंकार कर रहे हैं. ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ देशों में बड़े देशों की तुलना में 27 गुना कम वेतन दे रही हैं.

### बढ़ती हुई एकजुटता

परंतु इन और अन्य तमाम चालबाजियों के बावजूद दुनिया के कोने-कोने में मजदूरों और उनकी ट्रेड यूनियनों के बीच एकजुटता बढ़ रही है, एकता के महत्व की समझ बढ़ रही है तथा वैध और छोड़े न जा सकने वाले अधिकारों के लिए मजदूर वर्ग के संघर्षों की परिचायक हड़तालें, प्रदर्शन तथा विरोध काफी बढ़ चुके हैं.

दुनिया का मजदूर आंदोलन न केवल संख्या बल्कि क्षेत्र और गहराई की दृष्टि से भी बढ़ रहा है. आर्थिक समस्याओं और राजनैतिक आकांक्षाओं के बीच का संबंध ज्यादा से ज्यादा साफ होता जा रहा है. कुछ साल पहले अगर मजदूरी की मांगें मजदूर-हड़तालों के केंद्र में थी तो आज मजदूर आंदोलन बेकारी तथा छंटनी के खिलाफ और ट्रेड यूनियन अधिकारों तथा अपने-अपने देशों की स्वाधीनता और संप्रभुता की रक्षा के लिए, साम्राज्यवादी दखलंदाजी तथा हथियारों की दौड़ के खिलाफ और युद्ध उद्योग को शांति उद्योग में तब्दील करने, तनावशैथिल्य, निरस्त्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांतिपूर्ण समझदारी के लिए लड़ रहा है.

### चुनौतियों को स्वीकार करो

आज की दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है. आज हम मानव इतिहास के सबसे भयानक दौर से गुजर रहे हैं जबकि मानव मस्तिष्क और श्रम की तमाम उपलब्धियों सहित स्वयं मानव जाति के ही विनाश का खतरा पैदा हो गया है. यदि पिछला अनुभव हमारे कुछ काम का है तो हमें इस सच्चाई को समझ लेना चाहिए कि इस बार हमें अपनी गलतियों को सुधारने का दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है.

हमें जो चीज एक करती है, वह हैं, शान्ति की रक्षा में मानव जाति की गहरी रुचि, हथियारों की दौड़ के पागलपन के खिलाफ दृढ़ संघर्ष की जरूरत, एक बेहतर, श्रेस्ठतम, समतापूर्ण सुरक्षित तथा न्यायोचित जिन्दगी जीने की दुनिया भर के मजदूरों की आकांक्षा, विभिन्न देशों की जनता का आर्थिक तथा राजनैतिक आजादी हासिल करने का अधिकार, उपनिवेशवाद, नस्लवाद, फासीवाद, के खिलाफ दृढ़ संघर्ष की आकांक्षा, पूंजीवादियों तथा नव साम्राज्यवादी कूट के खिलाफ संघर्ष, नई और कहीं अधिक न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए विश्वव्यापी संघर्ष और अभी भी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रही जनता के साथ एकजुटता.

इतिहास हमें एक कर रहा है, हमारा भाग्य हमें एक कर रहा है, हमारा भविष्य हमें एक कर रहा है.

आइए हम अपनी पूरी ताकत के साथ मानव की रक्षा तथा सही अर्थों में मानव कहे जा सकने योग्य भविष्य के लिए संघर्ष करें.

दुनिया के सर्वहारा, एक हो!

# दसवां विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन

[पृष्ठ एक से आगे]

अल्पविकसित देशों के प्रतिनिधियों ने पूंजीवादी शासक वर्ग के दमन पर प्रकाश डाला. सभी ने एक तरफ से अमरीका को विश्व प्रतिक्रियावाद के पुलिस के रूप में निशाना बनाया. सब ने संयुक्त राज्य अमरीका को, शास्त्रों की दौड़ में बढ़ावा देने, बेमिसाल मिलिटरी बजट अपनाने, सामाजिक खर्चों में कटौती करने, दूसरे देशों के मामलों में खुला हस्तक्षेप करने तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों और मानवीय अधिकारों को कुचलने के लिए दौषी ठहराया

समाजवादी देशों के प्रतिनिधियों ने अमरीका द्वारा की जा रही युद्ध की तैयारियों के खिलाफ संघर्ष करने पर जोर दिया.

### भारत में संघर्ष

भारतवर्ष में हो रहे संघर्षों के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि "भारत सरकार द्वारा आवश्यक सेवाओं में हड़तालों को गैरकानूनी घोषित करने का निरंकुश अधिकार, जिसकी दौरान सारे उद्योगों को शामिल किया जा सकता है, हासिल कर लेने के खिलाफ विशाल विरोध कार्यवाहियां संगठित की गई. भारतवर्ष में ट्रेड यूनियन केंद्रों के द्वारा 23 नवम्बर को संसद पर 10 लाख मजदूरों की विशाल रैली का आयोजन किया गया तथा इसी विषय पर 19 जनवरी 1982 को देशव्यापी आम हड़ताल करने का आह्वान किया गया।" (चूंकि यह रिपोर्ट दिसम्बर 1981 में ही तैयार कर ली गई थी अतः उसमें हड़ताल की विस्तृत जानकारी शामिल नहीं की जा सकी. फिर भी हड़ताल के बाद विश्व ट्रेड यूनियन संघ ने सफल हड़ताल करने के लिए भारतीय मजदूर वर्ग को बधाई का तार भेजा है तथा हड़ताल को कुचलने के लिए सरकार द्वारा उठाए गये कदमों की निंदा की है.)

### प्रस्ताव और निर्णय

सम्मेलन ने राष्ट्रीय मुक्ति के लिए जनता के संघर्षो, लैटिन अमरीका और कैरीबियन, दक्षिण अफ्रीकी जनता के संघर्षों, अरब देशों, साइप्रस तथा कोरिया और अलसल्वाडोर आदि पर गई प्रस्ताव स्वीकार किए.

संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष अधिवेशन के साथ तालमेल रखकर जून माह को "शान्ति का महीना" के रूप मे मनाने का निर्णय लिया गया है. 1 सितम्बर को जिस दिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरूआत हुई थी, शान्ति और एकजुटता दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय किया गया है. सम्मेलन ने शान्ति और ट्रेड यूनियन अधिकार के सवाल पर क्षेत्रीय गोष्ठियों के आयोजन का भी निर्णय लिया है. दक्षिणी क्षेत्र के लिए गोष्ठी नबम्वर 1982 में दिल्ली में होंगी.

सेन्दोर गेस्यर और इब्राहिम जमारिया पुनः अध्यक्ष और महामंत्री चुने गये. □

# तमाम दुनिया की ट्रेड यूनियनों और मजदूरों के नाम दसवीं विश्व ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अपील

प्रिय भाइयों और बहनों,

10 से 15 फरवरी 1982 तक ह्वाना (क्यूबा) में हो रही दसवीं विश्व ट्रेड यूनियन कांग्रेस में सभी महाद्वीपों और समाज-व्यवस्थाओं के 26 करोड़ 90 लाख ट्रेड यूनियन सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले हम प्रतिनिधिगण आपका सादर अभिनन्दन करते हैं.

शान्ति की सुरक्षा, जीवन और कामकाज की परिस्थितियों की रक्षा और सुधार, ट्रेड यूनियन अधिकारों और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं को बरकरार रखने तथा विस्तृत करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके शानदार संघर्षों तथा संयुक्त कार्यवाहियों का हम स्वागत करते हैं.

इन वर्ग-युद्धों के मैदान में आपकी सफलताओं पर हम प्रसन्न है; हम आपके संघर्षों में अपनी एकजुटता की प्रतिज्ञा करते हैं; हम संयुक्त संघर्षों और एकजुटता की महान परम्पराओं को आगे बढ़ाने, मेहनतकशों के अधिकारों, लोकतांत्रिक प्रगति, शान्ति और जनता की सुरक्षा के खिलाफ बहुराष्ट्रीय निगमों, साम्राज्यवाद, नवउपनिवेषवाद और प्रतिक्रियावादी गुटों द्वारा संगठित हमलों के खिलाफ तमाम ट्रेड यूनियन ताकतों को और अधिक मजबूती के साथ संगठित करने की प्रतिज्ञा करते हैं. संयुक्त संघर्षों के अपने झण्डे को ऊंचा उठाते हुए हम मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियनों के सदस्यों को बांटने और तोड़फोड़ करने वाले तत्वों को अलग और परास्त कर देंगे.

इस सम्मेलन के माध्यम से हम आपको एकजुटता का सन्देश देते हैं. अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता के झण्डे को ऊंचा रखना, और मजदूरों की एकता ही अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आंदोलन की शक्ति के आधार हैं. यह एकता ही सफलता की गारण्टी है.

हम आपसे दुनिया की तमाम प्रगतिशील और साम्राज्य-विरोधी ताकतों से तमाम मजदूरों को संघर्ष के लिए संगठित करने हेतु और ज्यादा ताकत और दृढ़ता से काम करने की अपील करते हैं.

साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावाद के आक्रामक इरादों को काबू करने, विश्व आणविक विध्वंस को रोकने, हथियारों की दौड़ को रोकने तथा इस दौड़ में खर्च की जा रही भारी धनराशि को सामाजिक एवं आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण जरूरतों तथा विशेष रूप से अधिक रोजगार के मौके पैदाकर भारी बेरोजगारी की समस्या को हल करने के क्षेत्र में लगाने के लिए भारी ताकत और एकजुटता के साथ संघर्ष करने की जरूरत है.

बहुराष्ट्रीय उद्योगों और अन्य इजारेदारियों के मुनाफों और फैलाव के हित में सरकारों द्वारा अपनाई जा रही मजदूरविरोधी, समाजविरोधी नीतियों को बदलकर के मजदूरों और जनता के हितों में लोकतांत्रिक विकल्प लागू करने के लिए, भारी बेरोजगारी, ऊंची मुद्रास्फीति, बढ़ते हुए कर तथा विश्व मजदूर वर्ग को दुःखित करने वाली अन्य प्रतिगामी प्रवृत्तियों के खिलाफ संघर्ष करना होगा.

राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों, उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद, नस्लवाद, यहूदीवाद, रंगभेद, फासीवादी सैनिक तानाशाही तथा देशों के आन्तरिक मामलों में साम्राज्यवादी हस्तक्षेप के खिलाफ सघर्षों एवं नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सम्प्रभुता आर्थिक स्वतंत्रता के लिए हो रहे संघर्षों के समर्थन में एकजुटता को और ताकतवर बनाना होगा.

विशाल अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन सहयोग स्थापित करने और तमाम अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों को मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करने हेतु उचित रूप में एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करने हेतु जोरदार प्रयास की जरुरत है.

राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड यूनियन एकता स्थापित करने, एकजुट होकर साथ-साथ सम्पूर्ण मानव जाति के लिए एक बेहतर दुनियां के निर्माण तथा नवें दशक की चुनौतियों का सामना करने के लिए कठिन परिश्रम की दरकार है.

एकता ही हमारा शक्तिशाली हथियार रहे. एकजुटता हमारी शक्तिशाली ढाल है. एकता और एकजुटता के साथ आगे गढ़ते हुए हम अवश्य विजयी होंगे. □

# ा प्रतिरोध जारी

उपाध्यक्ष तथा सहायक मंत्री को -हड़ताल करने के लिए निलम्बित कर दिया है तथा बहुतों को आरोप पत्र दिया है.

हरिद्वार स्थित बी. एच. इ॰ एल में अभी भी 6 मजदूर निलम्बित हैं.

**पंजाब**

पेप्सू सड़क परिवाहन निगम में जब गिरफ्तार नेताओं को २० जनवरी को नही छोडा गया तब मजदूरों ने उनके रिहा किए जाने तथा काम पर वापस लिए जाने तक हड़ताल जारी रखी.

**डाक तार**

पोस्ट मास्टर जनरल ने 19 जनवरी को हड़ताल करने के लिए पश्चिम बंगाल के 6००० डाक तार कर्मचारियो का एक दिन का वेतन काटने तथा सेवा भंग करने का आदेश दिया है॰ इस दन्डात्मक कार्यवही के खिलाफ मजदूरों ने कठिन संघर्ष छेड़ दिया है.

**गैर कानूनी कैद**

बैंको तथा अन्य संगठनों ने गैरकानूनी गिरफ्तारियों तथा अन्य दमनात्मक कार्यवहियो की खबर दी है. सिवान (बिहार) में बैंक कर्मचारियो के नेता एस. एन चटर्जी को आधी रात में सोते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया तथा दो दिन तक हिरासत में रखा गया. कर्मचरियों ने २० ता. को भी हड़ताल रखी और अन्य संगठनो के साथ जिलाधीश के समक्ष प्रदर्शन किया. अन्त में चटर्जी को २२ ता. को जमानतपर रिहा कर दिया गया. उनके खिलाफ धारा 151 में एक झूठा केस दर्ज किया गया है. केस की वापसी के लिए अभी भी संघर्ष चल रहा है.

बिदिशा, इण्दौर, में जब बैंक और बीमा के तमाम कर्मचारी हड़ताल करने के बाद बाजार की तरफ जा रहे थे तो एक पुलिस अधिकारी ने पहुंचकर, मार्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव तथा प्रसिद्ध वकील सी. वाई. मुले को गिरफ्तार कर लिया. उनका कालर पकड़कर घसीटते हुए थाने ले जाया गया और लाठियों से पीटा गया. मजदुरों ने इसका बिरोध किया. इन्दौर, ग्वालियर तथा भोपाल आदि में वकीलों ने २1 ता. तक अदालतों का बहिस्कार किया. २1 ता. को मुले को बिना शर्त रिहा कर दिया गया. एक्सरे से पता चला है कि लाठियों के प्रहार से उनकी पसली की हड्डी टूट गई है.

**बिरोध दिवस**

हड़ताल के खिलाफ सरकार द्वारा उत्पीड़न दमन तथा अफवाहे फैलाए जाने के खिलाफ २3 फरवरी को बिशाल बिरोध प्रदर्शनों सभाओं, धरनों, जूलूसों के आयोजन के समाचार मिले हैं.

**संसद में**

लोकसभा में मा. क. पा. के नेता समर मुखर्जी ने २3 फरवरी को जरुरी जन महत्व के बिषय के अन्तर्गत इस सवाल को उठाया. उन्होने कहा कि, "भारतीय मजदूर वर्ग ने ट्रेड युनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति के अहवान पर एक दिन की देशब्यपी हड़ताल करके, सरकार की मजदूर बिरोधी, लोकतंत्र बिरोधी तथा मूल्य बृद्धि के खिलाफ अपना बिरोध प्रकट किया है. सरकार ने मजदूरों के साथ बात चीत करने के वजाय अपने नियतंण में प्रचार साधनों का खुला दुरुपयोग किया तथा दमनकारी नीतियां अपनाई. आज पूरे देश में हजारों हजार मजदूर बिशाल बिरोध सभाओं का आयोजन करके बिरोध दिवस मना रहे हैं. इस परिस्थिति की तरफ सरकार का ध्यान खीचते हुए हम सरकार से दमन समाप्त करने. दण्डात्मम कार्यवाहियों, ताकावन्दी, छटनी आदि को वापस लेने तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू करने का अनुरोध करते हैं."

**रा॰ अ॰ स॰ द्वारा सरकारी कदमों की निन्दा**

राष्ट्रीय अभियान समिति ने 10 मार्च को दिल्ली में हुई बैठक में मजदूरों के खिलाफ सरकार द्वारा अपनाई गई दमनात्मक कार्यवाहियों की निन्दा की है. कमेटी ने 23 फरबरी को सफलतापूर्वक देशव्यापी दमन विरोधी दिवस मनाने के लिए मजदूरों को बधाई दी है. कमेटी ने दमन वापस लेने के लिए प्रशासन को मजबूर करने की मजदूरों की सफलताओं का स्वागत किया है. तथा सरकार से समस्त दमन तुरन्त वापस लेने की मांग की है. समिति ने शानदार हड़ताल के लिए बम्बई के दो लाख कपड़ा-मिल मजदूरों को बधाई दी है तथा सरकार से हड़ताल संगठित करने वाली यूनियनों से समझौते के लिए शीघ्र बातचीत शुरू करने की मांग की है. रा. अ. स. ने भारत पेट्रोल निगम के तेल-शोधक कारखाने को, जिसके मजदूर 16 जनवरी से हड़लाल पर हैं, सेना के तकनीशियनों की मदद से चलाने के सरकार के प्रयासों की निन्दा की है.

**बजट और उत्पादन से जुड़े वेतन के खिलाफ**

रा. अ. स. ने इस वर्ष के वजट, रेल वजट नथा डाक सेवाओं की कीमतों में वढ़ोत्तरी आदि के द्वारा आम जनता पर 1300 करोड़ रुपये का बोझ लादने की निन्दा की है. मंहगाईभत्ते को जाम करने की सम्भावना भी इसके अलावा है. कमेटी ने इस्पात कोयला तथा अन्य उद्योगों में वेतन को उत्पादन से जोड़ने के लिए सार्वजनिक संस्थान ब्यूरों के निर्देशों की भी निन्दा की है. कमेटी ने जीवन स्तर पर हो रहे इन तमाम हमलों के खिलाफ जोरदार संघर्ष छेड़ने के लिए तमाम मजदूरों का आह्वान किया है. रा. अ॰ स. ने 16 अप्रैल को दिल्ली में राष्ट्रीय फेडरेशनों के साथ एक बैठक करने का निर्णय लिया है जिसमें 4 जून 81 के बम्बई सम्मेलन में उठाई गई मांगों को हासिल करने के लिए संघर्ष की अगली रूपरेखा तै की जायगी.


**आल इण्डिया कोल वर्कर्स फेडरेशन का सम्विधान**

**हिन्दी और अंग्रेजी में कीमत ६० पसे**

**आल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन**

**८७ अपकार गार्डेन, आसनसोल**

**पश्चिम बंगाल**

**से प्राप्त करें**

# श्रीलंका में आई० एल० ओ० की विचार सभा

कोलम्बो में 18 से 22 जनवरी तक श्रीलंका फाउण्डेशन इन्स्टीट्यूट के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आयोजित ट्रेड यूनियन प्रशिक्षकों के लिए शिक्षण विधि विषय पर क्षेत्रीय विचार गोष्ठी में सीटू की तरफ से डी० जानकी रामन ने हिस्सा लिया. इस गोष्ठी का आयोजन तूरिन सेन्टर (एशियाई क्षेत्र) के प्रशिक्षार्थियों के, मजदूर शिक्षण के क्षेत्र में, मूल्यांकन हेतु किया गया था. इस गोष्ठी में भारत, बंगलादेश, मलेशिया पाकिस्तान, सिंगापुर, थाईलैण्ड और श्रीलंका से 19 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. प्रतिनिधियों ने आई. एल. ओ. द्वारा पहले ही ट्रेड यूनियन केंद्रों को भेजी गई प्रश्नावली के आधार पर अपने लेख प्रस्तुत किए. गोष्ठी में प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री के स्तर को सुधारने के लिए तूरिन इन्टरनेशनल सेन्टर तथा सभी क्षेत्रों के कामगार प्रशिक्षण संस्थानों के बीच स्थाई रूप से विचार-विमर्श जारी रखने पर जोर दिया गया.

डी जानकीरामन ने अपनी रिपोर्ट में सीटू द्वारा 1979 से चलाए जा रहे कामगार प्रशिक्षण शिवरों का जिकर किया. उन्होंने इस बात का भी जिकर किया कि भारत सरकार के केन्द्रीय कामगार प्रशिक्षण परिषद ने प्रशिक्षार्थियों के लिए विषय-वस्तु और शिक्षक चुनने सम्बन्धी सीटू के सुझावों को स्वीकार कर लिया है. विचार-विमर्श में इस विषय पर सभी एकमत रहे कि इस को केवल प्रशिक्षार्थियों पर छोड़ देने के बजाय लक्ष्य को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए शिक्षण कार्यक्रम में ट्रेड यूनियन संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए.

# उत्पादन नीतियों की आलोचना

पेज तेरह से

बहुत अधिक राशि खर्च कर रहे हैं. प्रशासन समस्त ठेका मजदूरों को विभागीय करने के बजाय और भी ठेकेदारों को ठेका दे रहे हैं जबकि काम स्थाई तथा वर्षों तक चलने वाले है.

मजदूरों के स्वास्थ्य तथा काम से होने वाली बीमारियों के प्रति प्रशासन की निर्दयता पर भी विस्तार से चर्चा की गई. भिलाई के सदस्य ने धमन भट्ठी विभाग के एक मजदूर के शरीर से हाल में आपरेशन द्वारा निकाला गया कोयले का टुकड़ा दिखाया. सदस्यों ने मालिकों से इस्पात उद्योग में कार्यरत वातावरण का अध्ययन करने तथा उसमें सुधार करने के लिए शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध किया.

सदस्यों ने कैण्टीन में सामानों की आपूर्ति के गिरते स्तर की भी आलोचना की. स्थिति इतनी इतनी गम्भीर हो गई है कि मजदूरों ने केण्टीन कमेटी के चुनाव का बहिष्कार कर स्वयं कम्पनी के द्वारा कैण्टीन चलाए जाने की मांग की है.

अध्यक्ष ने अपने उत्तर में मजदूर प्रतिनिधियों द्वारा उठायी गई समस्याओं पर ध्यान देना स्वीकार किया.

सीटू की तरफ से एम के पन्धे, ए० कुमी अजीत मुखर्जी, पी के मुखर्जी तथा डी० भट्टाचार्या ने बैठक में हिस्सा लिया.

# वजीफे में वृद्धि

पृष्ठ सात से

का, जो कि इस परिषद के अध्यक्ष भी हैं, ध्यान परिषद द्वारा मनमाने ढंग से निर्णय लिए जाने की तरफ आकर्षित किया हैं. उन्होंने दावा किया है कि सिफारिशों में किसी भी प्रकार की रद्दोबदल करने से पहले परिषद से अवश्य विचार-विमर्श किया जाना चाहिए, अन्यथा त्रिपक्षीय कमेटियां आलोचना का विषय बनेगी. परिषद की बैठक शीघ्र ही बुलाने की भी मांग की गई है.

वित्त मंत्री को लिखे गए एक दूसरे पत्र में कहा गया है कि यह घपलेबाजी अवश्य ही वित्त मंत्रालय के इशारों पर की गई है और चूंकि सरकार स्वयं अपने प्रस्ताव से मुकर रही है, अतः वित्त मंत्रालय से हस्तक्षेप करने की मांग की गई हैं.

यह भी कहा गया है कि स्नातकों तथा तकनीकी प्रशिक्षुओं के लिए खेतिहर मजदूरों के लिए निर्धारित वेतन अनुसूचित रोजगार अथवा कारीगर प्रशिक्षुओं के लिए निर्धारित वजीफे से भी कम दर निर्धारित करना कितना हास्यास्पद है.

यूनियनें जब प्रशिक्षुओं के लिए निर्धारित वजीफे की दरों को लागू करवाने के लिए कदम उठाएं तो उन्हें स्नातक अथवा तकनीकी प्रशिक्षुओं के वजीफों की दरों में वृद्धि की मांग अवश्य उठानी चाहिए. □

# महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

| राज्य/केंद्र | 1981 नंव. | 1981 दिसं. | 1982 जन. |
|---|---|---|---|
| **बिहार** | | | |
| जमशेदपुर | 435 | 430 | 433 |
| झारिया | 442 | 440 | 436 |
| कोडर्मा | 497 | 490 | 494 |
| मोंघाइर | 513 | 496 | 484 |
| नोआमुंडी | 426 | 431 | 435 |
| **गुजरात** | | | |
| अहमदाबाद | 447 | 443 | 460 |
| भाव नगर | 462 | 464 | 462 |
| **हरियाणा** | | | |
| यमुना नगर | 493 | 487 | 489 |
| **जम्मू व काश्मीर** | | | |
| श्रीनगर | 497 | 477 | 477 |
| **मध्य प्रदेश** | | | |
| बालाघाट | 479 | 478 | 479 |
| भोपाल | 483 | 480 | 485 |
| ग्वालियर | 481 | 468 | 469 |
| इंदौर | 488 | 483 | 491 |
| **महाराष्ट्र** | | | |
| बंबई | 470 | 469 | 468 |
| नागपुर | 484 | 479 | 485 |
| शोलापुर | 508 | 521 | 530 |
| **पंजाब** | | | |
| अमृतसर | 485 | 472 | 467 |
| **राजस्थान** | | | |
| अजमेर | 478 | 483 | 488 |
| जयपुर | 491 | 493 | 496 |
| **उत्तर प्रदेश** | | | |
| कानपुर | 449 | 440 | 441 |
| सहारनपुर | 471 | 467 | 467 |
| वाराणसी | 505 | 496 | 495 |
| **पश्चिम बंगाल** | | | |
| आसन सोल | 464 | 467 | 462 |
| कलकत्ता | 426 | 426 | 419 |
| दार्जीलिंग | 379 | 378 | 382 |
| हावड़ा | 407 | 405 | 403 |
| जलपाइगुरी | 362 | 357 | 355 |
| रानीगंज | 441 | 451 | 446 |
| **दिल्ली** | 480 | 474 | 476 |
| **भारत** | 462 | 460 | 459 |

# सीटू की बिहार राज्य कमेटी की बैठक

सीटू की बिहार राज्य कमेटी की बैठक दि. 12-13 मार्च को पटना में हुई. बैठक की अध्यक्षता मुहम्मद इस्माइल ने की तथा सीटू सचिव एम. के. पन्धे भी बैठक में उपस्थित रहे. बैठक ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की दिल्ली राज्य कमेटी के सचिव तथा केन्द्रीय कमेटी के सदस्य जयपाल सिंह, संसद-सदस्य ज्योतिर्मय बसु तथा बिहार के कोयला और राख मजदूरों के नेता अरुन कुमार वर्मा के दुःखद निधन पर शोक प्रकट किया.

बैठक ने मूल्यवृद्धि, बढ़ती बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता, रेल भाडे एवं माल-भाडे में वृद्धि, डाकतार सामग्रियों की मूल्य-वृद्धि तथा जनविरोधी केन्द्रीय बजट पर विचार किया और चिन्ता जाहिर की. बैठक ने ट्रेड यूनियन आन्दोलन, पाकुर के पत्थर खदान मजदूरों, जमशेदपुर के ठेका मजदूरों तथा अन्य जगहों पर पुलिस के हमलों की निन्दा की. कोयला तथा इस्पात उद्योग में वेतन समझौते की तिथि की समाप्ति तथा वेतन को उत्पादकता से जोड़ने के सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, इस चुनौती का सामना करने के लिए दोनों उद्योगों के मजदूरों के राज्य सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया.

बैठक ने बिहार श्रम विभाग द्वारा विभिन्न उप-समितियों में सीटू को शामिल न किए जाने के खिलाफ इन्जीनियरिंग वेज बोर्ड के फैसलों को लागू करवाने तथा प्रेस मजदूरों के वेतन संबन्धी फैसलों के खिलाफ, जो कि वर्तमान वेतन से भी कम है प्रस्ताव पास किया.

बिहार न्यायिक अधिकारियों के संघर्ष का समर्थन करते हुए बैठक ने बिहार सरकार से चतुर्थ वेतन सुधार समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग की है.

सीटू ने राज्य के तमाम मजदूर वर्ग से जनतांत्रिक एवं ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने हेतु अपनी एकता को और सुदृढ़ करने तथा तमाम जनता के संघर्षों के समर्थन में जोरदार आन्दोलन खड़ा करने का आह्वान किया है. □

# शिमला होटल मजदूरों का दमन के खिलाफ संघर्ष

शिमला स्थित होटल 'विक्ट्री' के मजदूरों ने 8 मार्च को 4 सीटू कार्यकर्त्ताओं के दमन के खिलाफ एक दिन की हड़ताल की. दूसरे होटल के मजदूरों ने उनके समर्थन में प्रदर्शन किया.

हड़ताल करने से पूर्व मजदूरों ने उत्पीड़ित साथियों की बहाली के लिए कई दिनों तक क्रमिक भूख हड़ताल का आयोजन किया. मालिकों ने भूख हड़तालियों के टेन्ट उखड़वाने की कोशिश की परन्तु मजदूरों की एकता के कारण उनका षड़यंत्र सफल न हो सका.

7 मार्च को होटल के सामने गेट मीटिंग की गई जिसे एम. के. पन्धे, कपूर तथा धनीराम ने सम्बोधित किया. □

## सीटू के नामांकन

1. इण्डस्ट्रियल कमेटी आन प्लान्टेशन में सीटू का प्रतिनिधित्व करने के लिए के. पद्मनाभन, विमल रणदिवे तथा धनीराम खोसला को नामांकित किया गया है. पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की सरकारों के भी एक-एक प्रतिनिधि इस कमेटी में हैं.

2. बी. एच. ई. एल. नेगोशिएटिंग कमेटी में पी. राममूर्ति के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनकी जगह पर आर. उमानाथ को नामांकित किया गया है. □

# दिल्ली राज्य सीटू का सम्मेलन

दिल्ली 21 मार्च. सी० आई० टी० यू० की दिल्ली राज्य कमेटी का पहला सम्मेलन दिल्ली के कांस्टीच्यूशन हाल में सम्पन्न हुआ. सम्मेलन में राजधानी के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के कारखानों से आए 206 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. सम्मेलन की अध्यक्षता का० पूरन चंद, का० कमल नारायण और का० बच्चन सिंह ने की. का० सी० एन० सिंह ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया. दिल्ली राज्य सीटू के अध्यक्ष का० शादी राम ने ध्वजा रोहण किया.

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सीटू के अखिल भारतीय सचिव का० नृसिंह चक्रवर्ती ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर प्रकाश डाला और मजदूर वर्ग का आह्वान किया कि वह अपने दायित्व को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति से आगे बढ़ें. दिल्ली सीटू के सचिव का० जोगेन्द्र शर्मा ने संगठन की गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट पर हुई बहस में 25 प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

सम्मेलन द्वारा किए गये फैसले— सदस्यों में वृद्धि, व्यापक संयुक्त संघर्षों का निर्माण, तीन स्तरीय संगठन का विकास तथा सीटू मजदूर और वर्किंग क्लास की ग्राहक संख्या बढ़ाने से संबद्ध थे.

सम्मेलन ने 33 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव किया. का० पूरन चंद अध्यक्ष, का० सूरजभान महासचिव तथा का० सी० एन० सिंह कोषाध्यक्ष चुने गये. सम्मेलन का समापन दिल्ली राज्य सीटू के महासचिव का० सुशील भट्टाचार्य के भाषण के साथ हुआ. □


## सीटू मजदूर

एक प्रति की कीमत 50 पैसे
सालाना चंदा छः रुपये
कम से कम पांच प्रतियों की एजेंसी लिखें :

**सीटू कार्यालय**
**6, तालकटोरा रोड,**
**नई दिल्ली 110001**

# राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा मंहगाई, नगर तथा मकान भत्ता रोकने की निन्दा

**का०** डी० डी० वशिष्ठ (महामंत्री हिन्दमजदूर सभा), पार्वती कृष्णन (सचिव एटक) एम. के. पन्धे (सचिव सीटू) आर. के भगत (सचिव बी. एम. एस.), प्रतीश चन्द्रा (महासचिव यु. टी. यु. सी., ले. स.) सुशील भट्टाचार्या (उपाध्यक्ष यु. टी. यु. सी.) अमर प्रसाद चक्रवर्ती (संसद सदस्य तथा महासचिव टी. यु. सी. सी.) तथा जे. एस. दारा ने १६ मार्च को निम्नांकित बयान जारी किया.

राष्ट्रीय अभियान समिति सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की किश्तों कीं बकाया राशि को भविष्य निधि खाते में अनिवार्य रूप से जमा करने सम्बन्धी भारत सरकार के मनमाने निर्णय की तीव्र निन्दा करती है. इसी तरह से सरकार का यह निर्णय उपभोक्ता मूल्य सूची के 320 अंक तक महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल किए जाने से बढ़ने वाले मकान और नगर भत्ते पर भी लागू होगा. वास्तव में यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के ऊपर आंशिक वेतन और मंहगाई भत्ता-जाम थोपना है और यदि सरकारी कर्मचारी इसका कारगर तरीके से विरोध नहीं करते हैं तो यह भविष्य में भी दुहराया जायगा.

यद्यपि महंगाई भत्ते को बढ़ती कीमतों की भरपायी के लिए दी जाने वाली वैध धनराशि माना गया है, परन्तु सरकार ने मनमाने ढ़ंग से भत्ता अदा करने अथवा जमा रखने का अधिकार हासिल कर लिया है.

इस प्रकार भारत सरकार ने अनिवार्य जमा योजना को पीछे के दरवाजे से लागू कर दिया है. जब कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रहीं हैं, सरकार का यह कदम 80 लाख केन्द्रीय तथा 50 लाख राज्य सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को और भी नीचे गिराएगा.

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा आवश्यक सेवा अधिनियम की तलवारें कर्मचारियों के सर पर लटका कर सरकार उन्हें पूर्ण नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है.

राष्ट्रीय अभियान समिति वित्तमंत्री द्वारा संसद में दिए गये उस बयान की निन्दा करती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह केन्द्र सरकार तथा उसके कर्मचारियों के बीच का मामला है और सरकार इसमें केन्द्रीय ट्रेड युनियनों को हस्तक्षेप नहीं करने देगी. इस प्रकार उन्होंने मजदूर वर्ग के सही प्रतिनिधियों को राजनीतिक दलों की ट्रेड युनियन विंग कहकर निन्दा किया. कमेटी इस बात को स्पस्ट कर देना चाहती है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय अभियान समिति का हिस्सा है और वे आंशिक वेतनजाम थोपने के मनमाने निर्णय के खिलाफ हैं. राष्ट्रीय अभियान समिति इस हमले को सम्पूर्ण मजदूर वर्ग पर होने वाले हमले की पूर्वसूचना मानती है और तमाम ट्रेड युनियनों से केन्द्रीय सरकार के इस खतरनाक कदम का दृढ़ता से विरोध करने का आह्वान करती है जिससे कि इस मजदूर विरोधी कदम को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर किया जा सके.

# जूट मजदूरों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी

**प**श्चिम बंगाल के दो लाख जूट मजदूर, जूट मिल मालिकों द्वारा 1979 के विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करने के खिलाफ तथा पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम-मंत्री द्वारा संस्तुत वेतन क्रम एवं वेतनमान को लागू करवाने के लिए एक दिन की हड़ताल तथा उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं.

बंगाल चटकल मजदूर यूनियन के महासचिव कमल सरकार ने एक बयान में भारत सरकार की जूट मिल मालिकों को समर्थन देने की नीति की निन्दा की है. इन मालिकों ने 13 कारखानों में तालाबन्दी करके अथवा पूर्णबन्दी करके 15 हजार मजदूरों को बेरोजगार बना दिया है. मिलें खोलने के लिए मालिकों को मजबूर करने के बजाय भारत सरकार उन्हें, उद्योग में तथाकथित संकट को सुलझाने के लिए करोड़ों रुपये दे रही हैं. यूनियन की केन्द्रीय कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव में जे. के. जूट मिल कानपुर के हड़ताली मजदूरों के साथ एकजुटता प्रकट की है तथा उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार से मजदूरों की मांगें शीघ्र पूरी किए जाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है.

एक अन्य बयान में आल इण्डिया जूट वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव तथा संसद सदस्य नीरेन घोष ने जे. के. जूट मिल के मजदूरों का दमन करने के लिए सिंहनिया ग्रुप की तीव्र आलोचना की है तथा सिंहानिया की मजदूर-विरोधी नीतियों को समर्थन देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की निन्दा की है. उन्होंने गंगा जूट मिल वंसवारिया प० बंगाल का उदाहरण दिया, जहां कि सिंहनिया ने मिल में तालाबन्दी करके 7000 मजदूरों को बेरोजगार कर दिया.

कमल सरकार तथा नीरेन घोष दोनों नेताओं ने कच्चे जूट के व्यापार सहित तमाम जूट उद्योग के शीघ्र राष्ट्रीयकरण की मांग की है.

# चाय बागान मजदूरों द्वारा आन्दोलन

**चा**य बागान मजदूर यूनियन (सीटू) ने पश्चिम बंगाल के तमाम बागान मजदूरों से, मालिकों की मजदूर विरोधी कार्यवाहियों के खिलाफ 23 मार्च को विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया है. दार्जिलिंग, जालपाईगुडी तथा तराई के मालिकान कुछ दिनों पहले से मजदूरों के वर्तमान अधिकारों और सुविधाओं के मन्दी के बहाने छीनने की कोशिश करते रहे हैं. आवास की सुविधा देने, यहां तक कि मकानों की मरम्मत कराने से इंकार करना वेतन की कटौती, राशन देने से इंकार, समय से पूर्व जबरिया रिटायर करना, खाली जगहों को भरने से इंकार, बढ़ता काम का बोझ, अवैतनिक छुट्टी के लिए मजबूर करना, बोनस की अदायगी न करना तथा बन्द करने की धमकी आदि ने मजदूरों को संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है. यूनियन ने समस्त चाय बगान के मजदूरों से उस दिन संयुक्त संघर्षों की शुरूआत करने, अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त रैलियों, प्रदर्शनों सभाओं का आयोजन करने तथा बिल्ले लगाने की अपील की है.

## संकट का काला छाया

पृष्ठ दो से आगे

है जो कि लगातार दो वर्षों से 5000 करोड़ रुपये से ऊपर है. यह गतिरोध विकसित पूंजीवादी और साम्राज्यवादी देशों की सुरक्षात्मक नीतियों तथा बहुराष्ट्रीयों की लूट के कारण पैदा हुआ है. इजारेदारों तथा बहुराष्ट्रीयों के भारी मुनाफों पर आक्रमण से इंकार तथा उचित भूमिसुधार की कमी ने बहुसंख्यक मेहनतकश जनता को नंगा कर दिया है. किसान, खेतिहर मजदूर तथा मेहनतकश वर्ग अपने रहन सहन और कामकाज की स्थितियों पर इन आक्रमणों के खिलाफ लगातार खड़े हो रहे हैं.

### अधिनायकवादी मुहिम

सरकार ने जनता के संघर्षों को निर्दयतापूर्वक दबाने के लिए आवश्यक सेवा अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे कठोर हथियारों से अपने को लैस कर लिया है. गृहमंत्रालय ने 8 फरवरी को एक अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने के उद्देश्य से समस्त आर्थिक कार्यवाहियों को आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत 'आवश्यक' घोषित कर दिया है. यह सरकार का अधिनायकवादी आक्रमण है.

### भ्रष्टाचार

जैसा सभी जानते है कि भ्रष्टाचार अधिनायकवाद के साथ हाथ मैं हाथ मिलाकर चलता है. भ्रष्टाचार के एक के बाद दूसरे काण्ड लगातार प्रकाश में आ रहे हैं. डाकू सरकारी संरक्षण में खुला दरबार लगा रहे हैं. जब कि निर्दोष लोग ३० वर्षो से भी ज्यादा दिनों से हवालाती के रूप में जेलों में सड़ रहे है. शासक पार्टी के लोगों, पुलिस और अफसरशाही तथा असामाजिक तत्वों. तथा अपराधियों के बीच सम्बन्धों का प्रतिदिन पर्दाफाश हो रहा है. राज्यतंत्र की सडन अधिकाधिक प्रमाणित है. इसी पृष्ठभूमि में विपक्ष, न्यायपालिका तथा प्रेस पर आक्रमण को और तेज किया जा रहा है. राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली लागू करने तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारों में कटौती करने के प्रयास अक्षुण्ण रूप से जारीं है. समाज में नैतिक मूल्यों का अधोपतन सभी को प्रभावित कर रहा है.

### नीतियों में परिवर्तत के लिए संघर्ष

अतः मजदूर वर्ग को मूल्यवृद्धि तथा मजदूर विरोधी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपने संघर्षों को न केवल जारी रखना है बलिक उसे और धनीभूत करना चाहिए तथा नीतियों में परिवर्तन की मांग करनी चाहिए. पिछले 4 जून को बम्बई अधिवेशन के मध्यम से हासिल की गई महान एकता, जिसकी चरम परिणति 23 नवम्वर को संसद पर विशाल मजदूर रैली तथा 19 जनवरी 82 को ऐतिहासिक हड़ताल में हुई, को अभी और भी मजबूत किया जाना है. ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति- जिसकी बैठक अप्रेल माह के मध्य में होनी है—की जिम्मेदारी है कि अविच्छिन्न संघर्षों और कार्यवाहियों के लिए यथोचित कार्यक्रम तै करे. यह समय की आवश्यकता है और मजदूर वर्ग केवल स्वयं को खतरे में डालकर इसकी अवहेलना कर सकता है.

## स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के प्रबन्धकों की उत्पादन नीतियों की आलोचना

स्टील आथारिटी आफ इण्डिया के अध्यक्ष ने 5 मार्च 1982 को नई दिल्ली में उत्पादन पर हुई संयुक्त सभा में उत्पादन के क्षेत्र में आत्मतुष्टिपूर्ण रूपरेखा पेश की. उन्होंने इस बात का जिकर नहीं किया कि देश अभी भी विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा हिस्सा इस्पात के आयात पर क्यों खर्च कर रहा है, जबकि देश में इस्पात की उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग नहीं हो रहा है. वर्ष 1981-82 के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सके हैं. उन्होंने बिजली और कोयले की उचित आपूर्ति न होने को, इन लक्ष्यों के पूरा न होने का महत्वपूर्ण कारण बताया.

उन्होंने वर्ष 1982 के लिए 80.26 लाख लौहपिण्ड, 60.49 लाख टन विक्री योग्य स्पान, तथा 10.53 लाख टन कच्चा लोहा पैदा करने का लक्ष्य घोषित किया, तथा इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मजदूरों से सहयोग की मांग की.

मजदूर प्रतिनिधियों ने प्रबन्धकों द्वारा संयुक्त कमेंटी के अस्तित्व में होते हुए भी उनसे परामर्श किए वगैर लक्ष्य निर्धारित करने के तरीके की आलोचना की. दुर्गापुर स्टील प्लाण्ट में, पहले उत्पादन क्षमता का आंकलन गलत किए जाने की जानकारी के बावजूद ज्यादा लक्ष्य निर्धारित किए गये.

सदस्यों ने सभा की विषय सूची पहले से प्रसारित न किए जाने की भी आलोचना की, जिसके कारण सम्बन्धित विषयों पर वे पूरी तैयारी के साथ नहीं आ सके.

जब कि उद्योग बिजली संकट से गंभीर रूप से प्रभावित था, स्टील आथारिटी आफ इण्डिया का खुद का बिजली उत्पादन 1980-81 से काफी कम रहा. सदस्यों ने कहा कि अधिक इस्पात उत्पादन के लिए यह उत्पादन बढ़ना चाहिए. सदस्यों ने इस्पात उद्योगों के लिए अच्छे किस्म के कोयले की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा उठाए गये कदमों की जानकारी मांगी. सदस्यों के द्वारा इस्पात उद्योग में साधारण मानदण्ड से अधिक रिफ्रैक्ट्री खर्च की भी आलोचना की गई.

मजदूर प्रतिनिधियों ने प्रबन्धकों की औद्योगिक सम्बन्ध नीति की कटु आलोचना की. सार्वजनिक उद्योग संस्थान (**BPE**) द्वारा प्रबन्धकों को दिए गये, उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित किए जाने पर ही वेतन वृद्धि करने सम्बन्धि निर्देशों का सभी सदस्यों ने विरोध किया. ये निर्देश द्विपक्षीय वेतन-समझौतों की पवित्रता पर ही चोट करते हैं. सभी ट्रेड यूनियनों ने इन निर्देशों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया.

मजदूर प्रतिनिधियों ने बताया कि पिछले समझौते के बाद से इस्पात उद्योग में अकुशल तथा उच्च वेतन भोगी मजदूरों के वेतनों में क्रमशः 10% और 22% की कमी हुई है.

टाटा इस्पात कं० के सदस्य ने बताया कि वहां भर्ती पर पाबन्दी हटा लेने के बावजूद मजदूरों की कमी रही है. फिर भी प्रशासन मजदूरों की संख्या बढ़ाने के बजाय ओवरटाइम पर

पेज दस पर

## अध्यापिकाओं का सम्मेलन

केरल गवर्नमेन्ट टीचर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित महिला अध्यापिकाओं का एक सम्मेलन दि० 11-12 दिसम्बर को त्रिवेन्द्रम में सम्पन्न हुआ. राज्य के विभिन्न हिस्सों से 800 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया.

महिला फेडरेशन की प्रसिद्ध नेता, केरल सरकार की भूतपूर्व कृषि मंत्री के. आर. गौरी अम्मा ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए वर्तमान समाज-व्यवस्था में महिलाओं के भयानक शोषण का जिकर किया तथा सामन्तीं बेड़ियों के अवशेषों को समाप्त करने के लिए जुझारु संघर्ष करने के लिए महिला कार्यकर्त्ताओं का आह्वान किया. अपनी वास्तविक मुक्ति के लिए उन्हें आम मजदूर वर्ग के एक हिस्से के रूप में उभरना होगा. कामगार महिला समन्वय समिति की नेता मैथिलि सिवरामन ने सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए समस्त महिलाओं को, चाहे वे नौकरी-पेशा हों अथवा नहीं, संगठित करने के लिए प्रतिनिधियों का आह्वान किया.

केरला गवर्नमेन्ट टीचर्स एसोसिएशन, महिला विभाग की संयोयिका सोनी कामथ ने मांगपत्र पेश करते हुए कहा कि महिलाओं को एक साथ विविध प्रकार के कर्तव्य निभाने पड़ते हैं. वह एक पत्नी है, एक गृहणी है, मां है और मजदूर भी है. इस प्रकार विभिन्न कर्त्तव्यों को पूरा करने के बावजूद महिलाओं को बराबरी के सामाजिक न्याय से भी वंचित रखा जाता है. उन्होंने महिलाओं द्वारा ट्रेड यूनियन संघर्षों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लिए जाने पर जोर दिया. एन. जी. ओ. यूनियन महिला विभाग की संयोजिका एम. ओ. मल्लिका तथा विजय एस. मेनन एवं औरों ने भी अपने विचार रखे. साहित्यिक सत्र की अध्यक्षता उपन्यास लेखिका पी. वल्साला ने की तथा के. माधवीकुट्टी, पी. गोबिन्द पिल्लै एवं औरों ने सम्बोधित किया. प्रतिनिधियों ने म्युजियम जंक्शन से गान्धी पार्क तक एक जुलूस निकाला जहां एक आम सभा हुई. विधायिका भार्गवी थंकप्पन तथा अन्य लोगों ने भाषण दिए.

## अंतराष्ट्रीय महिला दिवस

इस वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ज्यादा उत्साह के साथ शांति पर जोर देकर मनाया गया. अखिल भारतीय गणतांत्रिक महिला संघ तथा कामगार महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति सहित 40 महिला संगठनों ने नई दिल्ली में इस दिवस को मनाया जिसमें सुशीला गोपालन (संसद सदस्या) तथा विमल रणदिवे ने भी हिस्सा लिया. सभा का विषय था, "शांति महिलाओं के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता तथा राष्ट्रीय उत्थान" महिलाओं की समस्याओं और शांति की रक्षा की आवश्यकता पर देशव्यापी जागृति पैदा करने के लिए अभियान चलाने संबंधी प्रस्ताव पास किया गया.

कलकत्ता में आयोजित इसी प्रकार की एक सभा में कनक मुखर्जी (संसद सदस्या) तथा पंकज आचार्य आदि गणतांत्रिक महिला समिति की नेताओं ने हिस्सा लिया. सभा ने महिलाओं के लिए शान्ति और सामाजिक विकास के लिए जोरदार अपील की.

## कमल सरकार रूसी ट्रेड यूनियन संघ की कांग्रेस में

आल यूनियन सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंस सोवियत रूस, के निमंत्रण पर दि० 17-20 मार्च 82 को मास्को में हो रही रूसी ट्रेड यूनियनों की 17वीं कांग्रेस में विरादराना प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेने के लिए सीटू ने कमल सरकार सीटू सचिव को नामांकित किया है. वे 13 मार्च को नई दिल्ली से रवाना हो गये.

यद्यपि इससे पूर्व मई दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए सीटू को आमंत्रित किया गया था, परंतु यह पहला अवसर है जब कि ए. यू. सी. सी. टी. यू. ने अपनी कांग्रेस में सीटू को आमंत्रित किया है. उनके निमंत्रण पर 1982 में एक दो सदस्यीय सद्भावना मण्डल मास्को गया था. यह ए. यू. सी. टी. यू तथा सीटू के बीच बढ़ते दोस्ताना संबधों का परिचायक है.

## वकीलों का अखिल भारतीय संघ

देश के समस्त हिस्सों में कानूनी पेशे में लगे लोगों के लगभग 300 प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में दि० 13-14 मार्च को दो दिन का सम्मेलन करके वकीलों का एक अखिल भारतीय संगठन बनाने का निर्णय लिया, जिसके लिए एक तैयारी कमेटी का गठन भी किया जा चुका है.

सम्मेलन की अध्यक्षता डेनियल लतीफी ने की तथा सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व जज एच. आर. खन्ना, वी. के. कृष्णा अय्यर और एस. पी. गुप्ता तथा औरों ने सम्मेलन को संबोधित किया. डेनियल लतीफी के नेतृत्व में अरुण प्रकाश चटर्जी, एन. एन. गुप्ता, हरदेव सिंह, उमेश मिश्रा, सुभाष चन्द्र विरला, आर. वी. सिंह, तथा अब्दुल हसीम आदि को लेकर संचालन समिति बनी. सीटू के उपाध्यक्ष तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति वसु (वार एट ला) ने भी समापन सत्र में भाषण दिया.

गहरे संकट की स्थिति में न्यायपालिका पर बढ़ रहे प्रहार की पृष्टभूमि में इस सम्मेलन का काफी महत्व है. सम्मेलन ने राष्ट्रपतीय ढांचे की सरकार लागू करने के प्रस्ताव के खिलाफ प्रस्ताव पास किया और आवश्यक सेवा अधिनियम की निंदा करते हुए गरीबों के लिए उचित कानूनी सहायता की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा. कानूनी पेशे में लगे लोगों की समस्याओं पर भी विचार किया गया. वकीलों के अखिल भारतीय संगठन के निर्माण के लिए सितंबर में एक बड़ा सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया.

15 मार्च को प्रतिनिधिगण सुप्रीम कोर्ट में एकत्रित हुए और वहां से बोट क्लब जाकर सरकार को एक स्मरण-पत्र दिया. समर मुखर्जी (संसद सदस्य) तथा सोमनाथ चटर्जी (संसद सदस्य) ने भी रैली को संबोधित किया.


**संपादक मंडल**

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति — मनोरंजन राय

नीरेन घोष — सुधीन कुमार

एम. के. पंधे (संपादक)

# बीमा कर्मचारियों का देशव्यापी आंदोलन

जीवन बीमा कर्मचारियों ने एल. आई.-सी. (एमेन्डमेन्ट) ऐक्ट 1981 को रद्द करने, 2 फरवरी और 27 जुलाई की अधिसूचनाओं को खतम कर सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को बहाल करने, तथा एल. आई. सी. के बंटवारे की योजना को निरस्त करने के लिए देश व्यापी संयुक्त कार्यवाही का कार्यक्रम बनाया है.

आल इण्डिया इन्स्योरेंस इम्प्लाईज एसोसिएशन, आल इण्डिया लाइफ इन्स्योरेन्स इम्प्लाईज ऐसोसिएशन, आल इण्डिया एल. आइ. सी. इम्प्लाईज फेडरेशन और नेशनल आर्गनाइजेशन आफ इन्स्योरेन्स वर्कर्स (बी. एम. एस.) के नेताओं ने एक संयुक्त बयान के द्वारा मजदूरों को इस बात की चेतावनी दी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्मचारियों की सेवा-शर्तों को तै करने का निरंकुश अधिकार देने वाले एल. आइ. सी. (एमेण्डमेण्ट) एक्ट को न्यायोचित करार देने के बाद सरकार सामूहिक सौदेवाजी की प्रक्रिया को जड़ से खत्म करना चाहती है. उन्होंने पुनः चेतावनी देते हुए बताया कि उनके अनेक बार मांग करने के बावजूद सरकर एल. आइ. सी. को बाट कर कर्मचारियों की एकता को तोड़ना चाहती है. उन्होंने कर्मचारियों से अपनी एकता को और मजबूत करने और एकजुट होकर इस कार्यक्रम को सफल करने का आह्वान किया है.

इस आन्दोलन कार्यक्रम में जनवरी १९७४ के सामूहिक समझौते का उल्लंघन करके अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने सम्बन्धी सरकार के आदेशों के खिलाफ 24 मार्च को एक घण्टे की वाक आउट हड़ताल भी शामिल है. यदि सरकार बंटवारे के लिए विधेयक प्रस्तुत करती है तो दो घण्टे की वाक आउट स्ट्राइक होगी तथा यदि सरकार सेवा-शर्तों को बदलती है तो उसी दिन एक दिन की हड़ताल होगी. कार्यक्रम में एल. आइ. सी. के बंटवारे के खिलाफ 10 लाख वीमा-धारियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. 2 अप्रैल को पूरे देश में मांग-दिवस मनाने तथा 17 अप्रैल को दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन करने का भी निर्णय किया गया.

---

पेज चार से

कर दिया था. अतः यह याचिका दाखिल की गई जिसमें उपरोक्त आदेश दिए गए हैं. प्रतिवादियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम. के. राममूर्ति तथा उमेश मिश्र आदि अधिवक्ताओं ने बहस की.

### अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में एल. आर. एस. ए. की शिकायत

आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के कार्यवाहक महासचिव टी. हनुमइया ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में इसके कनवेन्सन नं 1 के, जिसे भारत सरकार भी अनुमोदित कर चुकी है, उल्लंघन से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट दर्ज की है जिसमें काम के घण्टों के मामले में भारत के अन्य औद्योगिक मजदूरों की तुलना में रेल कर्मचारियों के साथ भेदभाव का व्यवहार करने तथा संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी से संबंधित कनवेन्शन नं० 87 और 98 के उल्लंघन का विस्तृत विवरण दिया गया है.

अपने जनवरी फरवरी 1981 के संघर्ष के संदर्भ में सीटू द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर "संगठन के लिए अधिकार समिति" की टिप्पणी को उद्धृत करते हुए उन्होंने विस्तार से बताया है कि किस तरह से अधिकारी 13 अगस्त 1973 से बार-बार समझौतों को एकतरफा तोड़ रहे हैं. उन्होंने संगठन बनाने के अधिकार को पैरों तले रौंदने के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं.

संगठन के लिए अधिकार समिति ने इस शिकायत की प्राप्ति स्वीकार की है और उसे केस नं० 1113 के रूप में दर्ज किया है तथा अतिरिक्त सूचनाएं और सहायक प्रमाण 29 मार्च तक भेजने का मौका दिया है.

सीटू के कोषाध्यक्ष तथा संसद सदस्य समर मुखर्जी ने इस शिकायत की एक प्रति श्रीमती इन्दिरा गांधी को भेजा है और यथोचित विचार करने का अनुरोध किया है.

### चीनी ट्रेड यूनियनों के संघ द्वारा सीटू को धन्यवाद ज्ञापन

प्रियों साथियों,

पिछली जनवरी में चीनी ट्रेड यूनियनों के महासंघ की सचिव परिषद के वैकल्पिक सदस्य का० हान सिया के नेतृत्व में चीनी ट्रेड यूनियनों का एक प्रतिनिधि-मण्डल आपके सुखद निमंत्रण पर इस्पात मजदूरों के अखिल भारतीय सम्मेलन में उपस्थित हुआ और भारतवर्ष की सद्भावना यात्रा की तथा चीनी मजदूरों और जनता के प्रति भारतीय मजदूरों और जनता की गहरी सद्भावना और दोस्ती की भावनाओं के साथ बीजिंग लौटा. चीनी ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि-मण्डल का उसके भारत प्रवास के दौरान गर्भजोशी के साथ स्वागत के लिए हम आपको हार्दिक धन्यवाद देते है.

चीनी ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि-मण्डल ने अपनी यात्रा के दौरान सीटू-नेताओं से मैत्रीपूर्ण वार्ता की, विभिन्न स्तरों पर सीटू कार्यकर्ताओं, किसानों, तथा विभिन्न पेशों के लोगों से सम्पर्क स्थापित किया और इस प्रकार आपसी समझ और दोस्ती में इजाफा किया. इन सब ने प्रतिनिधि-मण्डल पर एक अच्छा और गहरा प्रभाव डाला है.

भारत और चीन दोनों ही एशिया के महान देश हैं. दो देशों के बीच सम्बन्धों का सुधरना तथा हमारी ट्रेड यूनियनों और मजदूरों के बीच दोस्ताना सम्बन्धों को और मजबूत बनाना दोनो देशों की जनता और मजदूरों की सामान्य आकांक्षाओं की दृस्टि से ही आवश्यक नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण विश्व के मजदूर वर्ग के लिए और सम्पूर्ण विश्व तथा विशेष रुप से एशिया में शान्ति की रक्षा की दृस्टि से भी महत्वपूर्ण है. सीटू तथा भारतीय मजदूर वर्ग के साथ दोस्ताना सम्बन्धों को और आगे बढ़ाने के लिए हम आगे भी प्रयत्न करने की कामना करते हैं.

Regd. No. D(C) 833 CITU MAZDOOR

# बम्बई के कपड़ा मजदूरों की शानदार हड़ताल

बम्बई के 2 लाख कपड़ा मिल मजदूरों ने 18 जनवरी से अपने औजार रख दिए हैं. अब हड़ताल के दो महीने पूरे हो चुके हैं. यह हड़ताल, मालिकों की बढ़ती हुई लूट की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ द्वारा छोटे मोटे फायदों के लिए किए गये विश्वासघाती समझौते के खिलाफ बम्बई के मिल मजदूरों का विद्रोह है. महाराष्ट्र सरकार ने हड़ताल का आह्वान करने वाली यूनियों से बात करने का विरोध किया है इस बहाने कि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम के तहत एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन है. हड़ताल लम्बी होने का यही कारण है, और केन्द्रीय श्रम मंत्री भागवत झा आजाद महाराष्ट्र सरकार की ही तरफदारी कर रहे हैं जबकि उत्पादन में प्रतिदिन 4 करोड़ की हानि हो रही है.

बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने इस विश्वासघाती समझौते का विरोध करने तथा अन्तरिम सहायता के भुगतान की मांग के लिए पिछले वर्ष 27 सितम्बर को एक दिन की हड़ताल की थी. इंटक नेतृत्व ने इस हड़ताल का खुलकर विरोध यह कहकर किया था कि कपड़ा उद्योग में अधिक नौकरी की सम्भावनाएं हैं. हड़ताल पूर्णरूपेण सफल रही और मजदूरों ने मालिकों को यह बता दिया कि वे राष्ट्रीय मिल पजदूर संघ के साथ नहीं हैं. महाराष्ट्र सरकार ने मजदूरों की मनोदशा को समझने की बजाय मजदूरों के पीठ पीछे किए गये मजदूर विरोधी समझौते को खुला समर्थन दिया तथा गैरमान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ बातचीत करने से इंकार कर दिया.

बम्बई के इन्जीनियरिंग तथा रसायन उद्योग में हाल में हुए बहुत सारे समझौतों से मजदूरों के वेतन में 200-300 रु० प्रतिमाह की वृद्धि हुई है, अतः कपड़ा मजदूरों की इंटक समझौते से अधिक वेतन की मांग पूर्णरूपेण उचित है.

सफल हड़ताल के बाद राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के नेतृत्व ने बयान दिया कि राजेश और फोएनिक्स मिलों के मजदूर काम पर आने के लिए तैयार है परन्तु पुलिस सुरक्षा की उचित व्यवस्था न होने के लिए वे काम पर आने में असमर्थ हैं. 5 फरवरी को 500 पुलिसमैनों को लोवर परेल और फरगुशन रोड के बीच लगाया गया परन्तु कोई भी मजदूर काम पर जाने के लिए नहीं आया. इस प्रकार इंटक यूनियन बेनकाब हो गयी.

हड़ताल से पूर्व महाराष्ट्र पुलिस तथा रा० मि० म० स० के गुण्डों ने कोहिनूर मिल मजदूरों पर लाठी चार्ज किया, लेकिन सरकार ने केवल मजदूर-नेताओं को ही गिरफ्तार किया. इस दमन और गुण्डागर्दी के खिलाफ कपड़ा मजदूरों ने प्रदर्शन आयोजित किए.

लाल बावटा मिल मजदूर यूनियन (सीटू) ने हड़ताल के दौरान महाराष्ट्र तथा रा० मि० म० सं० की मालिकपरस्त नीतियों की निंदा करने के लिए कई सभाओं का अयोजन किया. इन सभाओं में बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया तथा संयुक्त संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ निश्चय का इजहार किया. यूनियन ने हड़ताल से सम्बन्धित विषयों पर एक पुस्तिका प्रकाशित की है और उसकी हजारों प्रतियां मजदूरों में बेची गई हैं.

मजदूरों की एकता और दृढ़ निश्चय ने महाराष्ट्र सरकार को विधान सभा में (यह घोषित करने के लिए मजबूर कर दिया कि वे हड़ताली मजदूरों की यूनियनों से बात करने के लिए तैयार हैं: फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता के बाद बम्बई के कपड़ा मजदूरों की इस सबसे लम्बी हड़ताल का हल ढूढ़ने की दृष्टि से बात-चीत करने के लिए उचित गम्भीरता के साथ कोई कदम नहीं उठाया.

# सीमेन्ट उद्योग के पंच फैसल पर स्थगन आदेश

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पंच फैसले की कार्यवाही को स्थगित करने का आदेश दिया है. सीमेन्ट उत्पादक संघ इंटक फेडरेशन के साथ किए गये इस समझौते को मजदूरों के ऊपर उनकी गैर जानकारी में सीटू तथा एटक आदि यूनियनों से सलाह किए वगैर लादने की कोशिश कर रहा था. इंटक फेडरेशन एक तरफ सीमेंट उद्योग में मजदूरों के लिए 1000 रु० न्यूनतम वेतन की मांग कर रहा था. और दूसरी तरफ इस पंच फैसले को स्वीकार कर लिया है. यह कितनी विचित्र बात है कि इंटक बिना संघर्ष के पंच समझौते से 1000 रु० न्यूनतम वेतन हासिल करने की आशा करती है.

सीटू ने सीमेन्ट उद्योग में समस्त संगठनों से मांगे हासिल करने के लिए संयुक्त-संघर्ष छेड़ने की अपील की है. भावी कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए सीटू यूनियन की बैठक 3 अप्रैल को मद्रास में होंगी.

(नोट :—पंच फैसले का समाचार जनवरी अंक में छप चुका है.)

# चीनी मजदूरों की सफल हड़ताल

न्योली सुगर फैक्ट्री कर्मचारी यूनियन (सीटू) एटा उ. प्र. ने अपनी 16 सूत्री मांगों को स्वीकार किये जाने को मांग करते हुए २8 फरवरी से अनिश्चित कालीन हड़ताल की नोटिश प्रशासन को दी. प्रशासन ने दमन के जरिए हड़ताल को रोकने की कोशिश की. परन्तु दो दिनो की सफल हड़ताल के बाद मालिकान उ. प्र. सीटू के अध्यक्ष हरसहाय सिंह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजदूर हो गये. सभी मांगे स्वीकार कर ली गई है.

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के लिए 6 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071)
से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी 52-53 डी.डीए. शेडस्, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित